वर्ष 13 • अंक 3 • 14 पृष्ठ • मूल्य 5 रुपये

बुधवार 19 फरवरी 2020

कोलकाता, चंडीगढ़, **नई दिल्ली**, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

पृष्ठ 6

गेहूं के रिकॉर्ड उत्पादन से भंडारण की होगी समस्या

पवन मुंजाल ▸▸ पृष्ठ 3

व्यापक बाजार के लिए लाएंगे ई-वाहन

डॉलर रु. 71.60 ▲ 30 पैसे | यूरो रु. 77.50 ▲ 20 पैसे | सोना (10ग्राम) रु 40970 ▲ 269 रुपये | सेंसेक्स 40894.40 ▼ 161.30 | निफ्टी 11992.50 ▼ 53.30 | निफ्टी फ्यूचर्स 12006.10 ▲ 13.60 | ब्रेंट क्रूड 56.20 डॉलर ▼ 01.20 डॉलर

एक नज़र

दूरसंचार संकट पर सरकार सक्रिय, सचिवों से मंत्रणा

दूरसंचार संकट को लेकर सरकार में हलचल बढ़ गई है। मंगलवार को वोडाफोन आइडिया के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला ने एजीआर भुगतान से उपजे संकट को लेकर दूरसंचार सचिव से मुलाकात की। शाम को कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद भी प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे। समझा जाता है कि उन्होंने प्रधानमंत्री से इस मसले पर चर्चा की। देर शाम प्रसाद के घर पर दूरसंचार सचिव, आईटी सचिव और विधि सचिव मंत्रणा करने पहुंचे। बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक प्रस्तावित है, जिसमें इस मसले पर विचार किया जा सकता है। यह भी अटकल है कि सरकार संकट दूर करने के लिए अध्यादेश ला सकती है।

खर्च में कटौती करें बीमा कंपनियां: खुंटिया

भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के चेयरमैन सुभाष चंद्र खुंटिया ने कहा है कि सामान्य बीमा कंपनियों को कीमतों में बढ़ोतरी पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय बट्टे खाते के घाटे से बाहर निकलने के लिए अपने खर्च में कटौती करने, कार्यकुशलता में सुधार करने और बेहतर उत्पाद का डिजाइन करने पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। ज्यादातर सामान्य बीमा कंपनियां बट्टे खाते का घाटा दिखा रही हैं और अपने कारोबार चलाने के लिए धन का प्रबंधन आमदनी के अन्य स्रोतों और निवेश से होने वाली आमदनी से कर रही हैं। पृष्ठ 4

जेऐंडजे के खिलाफ जारी जुर्माना नोटिस पर रोक

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण (एनएपीए) द्वारा जॉनसन एंड जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड पर जुर्माना लगाने के लिए जारी 'कारण बताओ नोटिस' पर रोक लगा दी। एनएपीए ने कंपनी को कथित रूप से सेनेटरी नैपकिन पर कर घटने के बावजूद खरीदारों को उसका लाभ नहीं देने के लिए जुर्माना लगाया था। न्यायालय ने 24 सितंबर को सुनवाई की अगली तारीख तक अमेरिकी कंपनी की भारतीय शाखा के खिलाफ किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई शुरू नहीं करने का आदेश दिया।

पाकिस्तान को संदिग्ध सूची में ही रखने की सिफारिश

आतंकवादियों के वित्त पोषण पर नजर रखने वाले वैश्विक इकाई एफएटीएफ के एक उप-समूह ने मंगलवार को वित्त पोषण पर काबू पाने में नाकाम रहने के कारण पाकिस्तान को संदिग्ध सूची (ग्रे लिस्ट) में ही रखने की सिफारिश की। सूत्रों के अनुसार इस संबंध में अंतिम निर्णय 21 फरवरी को लिया जाएगा। यह निर्णय एफएटीएफ के अंतरराष्ट्रीय सहयोग समीक्षा समूह (आईसीआरजी) की बैठक में लिया गया। इस संबंध में अंतिम फैसला शुक्रवार को किया जाएगा, जब एफएटीएफ पाकिस्तान पूरे मुद्दों पर गौर करेगा।

एचएसबीसी बैंक कारोबार का करेगा पुनर्गठन

एचएसबीसी बैंक ने मंगलवार को अपने कारोबार का तर्कसंगत पुनर्गठन करने की घोषणा की। बैंक अपनी इस योजना के तहत 35,000 लोगों की छंटनी कर सकती है। बैंक का लाभ लगातार तीन वर्षों से कम होता जा रहा है। बैंक का कहना है कि वह अपने बैंक के यूरोप और अमेरिका के कारोबार का दायरा भी घटाएगा। वैश्विक स्तरों पर विभिन्न घटनाक्रमों के बीच बैंक अनिश्चितताओं का सामना कर रहा है।

संकट से निपटने के होंगे उपाय

कोरोनावायरस की वजह से कच्चे माल की आवक हो रही प्रभावित, वित्त मंत्री ने की बैठक

अरूप रायचौधरी और सोमेश झा
नई दिल्ली, 18 फरवरी

चीन में फैले कोरोनावायरस की वजह से माल की आवाजाही में हो रही दिक्कत को देखते हुए सरकार जल्द ही कुछ उपायों की घोषणा कर सकती है। विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार बंदरगाहों और माल की आवाजाही से संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए तत्काल जरूरी उपाय करेगी। बंदरगाहों पर माल की मंजूरी में तेजी लाई जाएगी और इसके लिए चौबीसों घंटे कर्मचारी काम पर लगाए जाएंगे।

फार्मा, स्वास्थ्य और सर्जिकल उपकरण, रसायन, पेंट एवं उर्वरक, परिधान, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी हार्डवेयर, वाहन, दूरसंचार, मोबाइल उपकरण विनिर्माता और स्टील आदि क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने आज वित्त मंत्री और सरकार के सचिवों से मुलाकात की।

सूत्रों के अनुसार कुछ क्षेत्रों ने चीन से कच्चा माल नहीं आने या बंदरगाहों पर उसके फंसे होने को लेकर चिंता जताई। माल की खेप बंदरगाहों पर अटकी हुई है क्योंकि चीन के अधिकारी समुचित कागजात मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है कि चीन में अधिकांश अधिकारी कोरोनावायरस से निपटने के काम में लगे हैं। हालांकि चेन्नई बंदरगाह पर कागजात में कुछ छूट दी गई है जिसे अन्य बंदरगाहों पर भी लागू किया जा सकता है।

- लॉजिस्टिक्स और माल की आवाजाही को सुगम बनाने के होंगे उपाय
- एमएसएमई को कर्ज में राहत देने की भी हो सकती है घोषणा
- फार्मा, रसायन, समुद्री उत्पाद जैसे क्षेत्रों पर पड़ रहा है ज्यादा असर
- आवश्यक फार्मा उत्पादों के फॉर्मूलेशन हो सकते हैं एयरलिफ्ट
- प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ चर्चा करेंगी वित्त मंत्री

समुद्री खाद्य पदार्थों से जुड़ उद्योग के प्रतिनिधियों ने कहा कि दक्षिण पूर्व एशिया और चीन उनका बड़ा आयातक है लेकिन वहां निर्यात नहीं होने की वजह से मुश्किल आ रही है। फार्मा और रसायन उद्योग से जुड़े लोगों ने कहा कि कच्चे माल की किल्लत की वजह से उनके उत्पादन पर असर पड़ रहा है।

वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि स्थिति से निपटने के लिए सरकार विभिन्न उपायों पर विचार कर रही है, जिनमें एसएमई क्षेत्र को कर्ज में राहत देने के उपाय भी शामिल हैं। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि तमाम क्षेत्रों की कंपनियां चीन के अपने आपूर्तिकर्ताओं और साझेदारों के मामले में 'फोर्स मेज्योर' प्रावधान का उल्लेख करेंगी। आम तौर पर अनुबंधों में यह प्रावधान रखा जाता है जो किसी भी प्राकृतिक आपदा या अवंचनीय स्थिति पैदा होने पर संबंधित पक्षों को सभी तरह के दायित्वों से मुक्त कर देता है।

अहम बात यह है कि सरकार ऐसे बुनियादी औषधि उत्पादों और कच्चे माल को हवाई मार्ग से लाने के बारे में सोच सकती है जिन पर सीमा शुल्क कम है या एकदम नहीं लगेगा। सच तो यह है कि भारत सक्रिय दवा सामग्रियों के लिए चीन से होने वाले आयात पर बुरी तरह निर्भर है।

सीतारमण ने कहा कि वित्त मंत्रालय के तमाम विभागों के सचिव अलग-अलग क्षेत्रों का जायजा लेंगे और संबंधित मंत्रालयों के सचिवों के साथ बात कर उन्हें उस उद्योग के हिसाब से समाधान सुझाएंगे। उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार कोरोना वायरस का प्रकोप फैलने से पैदा हुई अनचाही स्थिति से निपटने के लिए तात्कालिक एवं मध्यावधि उपायों का ब्लूप्रिंट लेकर आएगी।

पीएफसी और आरईसी के विलय में फंसा पेच

श्रेया जय
नई दिल्ली, 18 फरवरी

- सरकार अन्य पीएसयू को कंपनी में हिस्सेदारी लेने को कह सकती है
- पिछले साल पीएफसी ने आरईसी में खरीदी थी सरकार की 52.63 फीसदी हिस्सेदारी
- एकीकृत इकाई में सरकार की हिस्सेदारी 51 फीसदी से कम होने का जोखिम

बिजली क्षेत्र गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) पावर फाइनैंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) द्वारा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन (आरईसी) में सरकार की हिस्सेदारी खरीदे जाने के एक साल बाद भी दोनों कंपनियों के विलय की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। इस बीच पीएफसी और आरईसी के वैश्विक ऋणदाताओं ने देरी और विलय के बाद कंपनी के ढांचे को लेकर आगाह किया है।

पीएफसी ने पिछले साल मार्च में आरईसी में सरकार की 52.63 फीसदी हिस्सेदारी के साथ ही प्रबंधन का नियंत्रण हासिल किया था। अधिग्रहण की कुल लागत 14,500 करोड़ रुपये थी। इस विलय के जरिये केंद्र सरकार पिछले वित्त वर्ष में विनिवेश से 85,000 करोड़ रुपये जुटाने में सक्षम हुई थी। पीएफसी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक राजीव शर्मा ने उस समय कहा था कि दोनों कंपनियों का विलय 2019-20 में पूरा हो जाएगा। इस बारे में हमें सरकार से निर्देश मिले हैं।

इस सौदे से कंपनी में केंद्र की हिस्सेदारी 51 फीसदी से नीचे हो गई। इसलिए सरकार अब सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य कंपनियों जैसे एलआईसी, एनटीपीसी से एकीकृत कंपनी में हिस्सेदारी लेने के लिए संपर्क किया है। एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि विलय की वजह से कंपनी में सरकार की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी घटकर 38 से 45 फीसदी रह सकती है। एक सूत्र ने कहा, 'कई संस्थागत निवेशकों ने पीएफसी और आरईसी को इसलिए कर्ज दिया है क्योंकि इसमें बहुलांश हिस्सेदारी सरकार के पास थी। ऐसे में अगर कंपनी में सरकार का हिस्सा 51 फीसदी से कम होता है तो वे अनुबंध का उल्लंघन का तर्क देकर निवेश निकाल सकते हैं।' उन्होंने कहा कि कई वैश्विक ऋणदाताओं ने उधारी दर बढ़ाने और निवेश कम करने के संकेत भी दिए हैं।

पीएफसी और आरईसी की कुल बाह्य उधारी करीब 10 अरब डॉलर है। अधिग्रहण प्रक्रिया से जुड़े एक वरिष्ठ कार्याधिकारी ने कहा, 'सार्वजनिक कंपनियों जैसे कि एलआईसी, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, एनएचपीसी आदि को एकीकृत इकाई में हिस्सा लेने को कहा जा सकता है ताकि उक्त कंपनी में परोक्ष तौर पर सरकार की हिस्सेदारी बढ़ सके।'

एकीकृत कंपनी में अपनी हिस्सेदारी 51 फीसदी करने के लिए केंद्र सरकार को करीब 7,000 से 10,000 करोड़ रुपये लगाने पड़ेंगे।

दिल्ली का बजट 12 से 15 फीसदी बढ़ेगा!

रामवीर सिंह गुर्जर
नई दिल्ली, 18 फरवरी

केजरीवाल सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होली बाद पेश करने जा रही है। दिल्ली के वित्त मंत्री ने अधिकारियों को बजट तैयार करने को कहा है। आगामी वित्त वर्ष के इस बजट में चालू वित्त वर्ष के बजट के मुकाबले 12 से 15 फीसदी इजाफा हो सकता है। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ ही परिवहन और प्रदूषण नियंत्रण पर विशेष जोर दिया जा सकता है। बजट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दी गई 10 गारंटी के साथ आप के घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने के लिए प्रावधान किए जा सकते हैं। इस बीच, दिल्ली के नवनियुक्त पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने गुरुवार को प्रदूषण नियंत्रण के उपायों पर चर्चा करने के लिए उच्चस्तरीय बैठक बुलाई है।

67,000 करोड़ रुपये से अधिक व्यय वाला होगा बजट, चालू बजट 60,000 करोड़ रुपये व्यय का

शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ प्रदूषण नियंत्रण व परिवहन मजबूत करने पर खास जोर

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने प्रदूषण नियंत्रण पर चर्चा करने बुलाई उच्चस्तरीय बैठक

दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अधिकारियों को बजट की तैयारी करने को कहा है। इसके बाद विभागों से बजट प्रस्ताव मंगाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। दिल्ली सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए 60,000 करोड़ रुपये खर्च वाला बजट पेश किया था। अगले वित्त वर्ष के लिए अगले माह पेश होने वाले बजट में 12 से 15 फीसदी इजाफा हो सकता है। बजट 67,000 करोड़ रुपये से अधिक व्यय वाला हो सकता है। बजट में परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नई बसों की खरीद के लिए पर्याप्त राशि आवंटित हो सकती है। बजट में ई-वाहनों और प्रदूषण नियंत्रण उपायों पर विशेष जोर दिया जा सकता है। पिछले बजटों की तरह शिक्षा-स्वास्थ्य पर प्राथमिकता जारी रहेगी।

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रदूषण की समस्या पर कार्ययोजना बनाने के लिए गुरुवार को उच्च अधिकारियों की एक बैठक बुलाई है। सर्दियों के दौरान दिल्ली में प्रदूषण कैसे कम किया जाए इस विषय पर पर्यावरण विभाग के उच्च अधिकारियों को अपनी योजना का खाका प्रस्तुत करने को कहा गया है।

वॉलमार्ट की बिक्री बढ़ी

वॉलमार्ट ने कहा है कि वित्त वर्ष 2020 में उसकी अंतरराष्ट्रीय शुद्ध बिक्री में 2.8 फीसदी की वृद्धि हुई है। कंपनी ने कहा है भारत, मेक्सिको और चीन से कारोबार को ताकत मिली। पृष्ठ 2

दशक में सबसे कम रहेगी वेतन वृद्धि

संजय कुमार सिंह
नई दिल्ली, 18 फरवरी

अर्थव्यवस्था में नरमी का असर भारतीय उद्योग जगत में वेतन वृद्धि पर भी दिख रहा है। वैश्विक पेशेवर सेवा फर्म एऑन पीएलसी के सालाना वेतन वृद्धि सर्वेक्षण के अनुसार 2020 में औसत वेतन वृद्धि 9.1 फीसदी रहने का अनुमान है जो इस दशक में सबसे कम है। 2008 के वित्तीय संकट के बाद वेतन वृद्धि घटकर 6.6 फीसदी रह गई थी। हालांकि अच्छी खबर यह है कि सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर कम रहने के अनुमान के बावजूद 2020 में औसत वेतन वृद्धि में पिछले साल की तुलना में केवल 20 आधार अंक की कमी आ सकती है। वैसे, दो अंकों में वेतन वृद्धि की आस पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। देश में भले ही औसत वेतन वृद्धि में कमी आ सकती है लेकिन 39 फीसदी संस्थान 2020 में अपने कर्मचारियों को दो अंकों में वेतन वृद्धि का तोहफा दे सकते हैं।

इस साल के आंकड़ों को दीर्घावधि रुझान को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। एऑन के भारत में पार्टनर एवं रीवार्ड्स सॉल्यूशंस की प्रमुख ज़ीटेल फर्नांडिस ने कहा, 'पिछले कुछ साल से वेतन वृद्धि में कमी का रुख बना हुआ है। 2011 में औसत वेतन वृद्धि दो अंक के उच्च स्तर पर थी। लेकिन 2012 से 2016 के बीच यह 10 फीसदी के आसपास रही और हाल के वर्षों में यह घटकर 9 फीसदी के करीब रह गई है।' उन्होंने कहा कि इस साल फर्मों के बीच सतर्कता देखी जा रही है। एऑन के सर्वेक्षण में 20 उद्योगों से जुड़ी 1,000 से ज्यादा कंपनियों को शामिल किया गया। इनमें विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की फर्में समान रूप से शामिल हैं।

- एऑन के सर्वेक्षण के अनुसार इस साल औसतन 9.1 फीसदी रह सकती है वेतन वृद्धि
- 39 फीसदी फर्मों की योजना 10 फीसदी या अधिक वेतन वृद्धि करने की है

2020 में सर्वेक्षण में शामिल 92 फीसदी कंपनियों ने बताया कि उनके कारोबार में सुधार हो रहा है या वह स्थिर है। अर्थव्यवस्था में नरमी के बावजूद अधिकांश फर्मों ने बताया कि वह इस साल पिछले साल की तुलना में थोड़ा बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। दूसरा रुझान यह देखने को मिला कि लगभग सभी क्षेत्रों में वेतन वृद्धि के दायरे में अंतर कम हुआ है। 2020 में ई-कॉमर्स, पेशेवर सेवा संस्थानों ने औसतन 10 फीसदी वेतन वृद्धि की पेशकश की योजना बताई थी जबकि लॉजिस्टिक्स, परिवहन क्षेत्र में 7.6 फीसदी इजाफा होने की बात कही गई थी। एऑन में निदेशक -प्रदर्शन एवं रीवार्ड्स नवनीत रत्तन ने कहा, '2011 से पहले आईटी, दूरसंचार, रिटेल और वित्तीय सेवा क्षेत्रों की वजह औसत वेतन वृद्धि में इजाफा होता था। लेकिन अब सभी क्षेत्रों में समान स्थिति है।' बजट कम होने से वेरिएबल वेतन का हिस्सा कुल तय वेतन में बढ़ा है। 2018 में यह 15.2 फीसदी था जो 2019 में बढ़कर 16.1 फीसदी हो गया। वरिष्ठ प्रबंधन स्तर पर यह 23.4 फीसदी और कनिष्ठ प्रबंधन स्तर के लिए 11.4 फीसदी था।

खबरों में रहे स्टॉक

जेएसडब्ल्यू एनर्जी

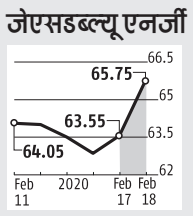

ओडिशा में जीएमआर की बिजली परियोजना का अधिग्रहण करेगी

₹ 63.55 पिछला बंद भाव
₹ 65.75 आज का बंद भाव

▲ 3.46 %

हैथवे केबल ऐंड डेटाकॉम

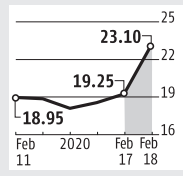

आरआईएल ने मीडिया एवं वितरण कारोबार को सुदृढ़ करने की घोषणा की

₹ 19.25 पिछला बंद भाव
₹ 23.10 आज का बंद भाव

▲ 20.00 %

भारती एयरटेल

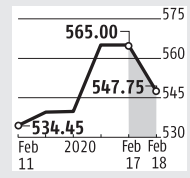

एसऐंडपी बीएसई सेंसेक्स में सबसे अधिक गिरने वाला शेयर

₹ 565.00 पिछला बंद भाव
₹ 547.75 आज का बंद भाव

▼ 3.05 %

इंडसइंड बैंक

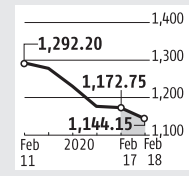

मूडीज द्वारा परिदृश्य नकारात्मक किए जाने के बाद 14 फीसदी की गिरावट

₹ 1,172.75 पिछला बंद भाव
₹ 1,144.15 आज का बंद भाव

▼ 2.44 %

आईआरसीटीसी

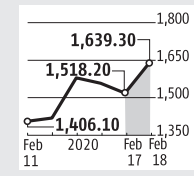

तीसरी निजी ट्रेन का परिचालन 20 फरवरी से

₹ 1,518.20 पिछला बंद भाव
₹ 1,639.30 आज का बंद भाव

▲ 7.98 %

संक्षेप में

निफ्टी में येस बैंक की जगह लेगी श्री सीमेंट

निफ्टी-50 इंडेक्स में येस बैंक की जगह श्री सीमेंट लेगी। यह बदलाव 27 मार्च से प्रभावी होगा। इसके साथ ही श्री सीमेंट ब्लूचिप कंपनी के इंडेक्स में सीमेंट विनिर्माताओं के तौर पर अल्ट्राटेक सीमेंट के साथ होगी। कोलकाता की इस कंपनी ने डाबर और गोदरेज कंज्यूमर प्रॉडक्ट्स को पीछे छोड़ दिया, जो इंडेक्स में शामिल किए जाने के मामले में सबसे आगे चल रही थीं। तीनों कंपनियों में श्री सीमेंट का सार्वजनिक बाजार पूंजीकरण सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह नवंबर में 3,000 करोड़ रुपये की पूंजी जुटाया जाना है। *बीएस*

ऐबट इंडिया के प्रबंध निदेशक ने दिया इस्तीफा

ऐबट इंडिया के प्रबंध निदेशक अंबाती वेणु ने इस दवा कंपनी में पांच साल काम करने के बाद इस्तीफा दे दिया है। रॉयटर्स ने यह जानकारी दी है। ऐबट ने वेणु को सितंबर 2016 में प्रबंध निदेशक नियुक्त किया था। वह ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंज्यूमर हेल्थकेयर छोड़कर ऐबट से जुड़े थे, जहां उन्होंने 24 साल से ज्यादा समय काम किया था। *बीएस*

वॉलमार्ट की अंतरराष्ट्रीय बिक्री बढ़ी

कंपनी को भारत, मेक्सिको और चीन से मिली ताकत, अंतरराष्ट्रीय बिक्री 2.8 फीसदी बढ़ी

पीरजादा अबरार
बेंगलूरु, 18 फरवरी

विश्व की सबसे बड़ी खुदरा कंपनी वॉलमार्ट ने कहा है कि वित्त वर्ष 2020 में स्थिर मुद्रा पर उसकी अंतरराष्ट्रीय शुद्ध बिक्री में 2.8 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई जिसे भारत, मेक्सिको और चीन से ताकत मिली। वर्ष 2020 के लिए कुल राजस्व 9.6 अरब डॉलर यानी 1.9 फीसदी बढ़कर 524 अरब डॉलर हो गया। मुद्रा को छोड़कर कुल राजस्व 528.1 अरब डॉलर रहा जो 13.7 अरब डॉलर यानी 2.7 फीसदी की वृद्धि दर्शाता है।

वॉलमार्ट के अध्यक्ष एवं सीईओ डौ मैकमिलन ने एक बयान में कहा, 'चौथी तिमाही में हमने मेक्सिको, भारत और चीन में ताकत के अलावा ई-कॉमर्स और सैम्स क्लब के साथ अमेरिका में दमदार प्रदर्शन किया।' अमेरिका के बाहर कंपनी के कारोबार की देखरेख करने वाली इकाई वॉलमार्ट इंटरनैशनल ने चौथी तिमाही में अपनी श्रेणी की कुल बिक्री में ई-कॉमर्स का योगदान 12 फीसदी दर्ज किया। इसे फ्लिपकार्ट और कई बाजारों में किराने के सामान की ऑनलाइन बिक्री से बल मिला। तिमाही के दौरान कुल राजस्व 141.7 अरब डॉलर रहा जो 2.9 अरब डॉलर यानी 2.1 फीसदी अधिक है। मैकमिलन ने 2020 इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी मीटिंग के दौरान कहा, 'जहां तक भारत का सवाल है तो वहां मौजूद अवसरों को लेकर हम काफी रोमांचित हैं। फ्लिपकार्ट और फोनपे (डिजिटल भुगतान फर्म) ने जिस तरीके से कारोबार का विस्तार किया है वह काफी आकर्षक है।'

भारत के ऑनलाइन खुदरा बाजार में वॉलमार्ट ने 2018 में 16 अरब डॉलर के एक सौदे के तहत फ्लिपकार्ट के अधिग्रहण के साथ ही प्रमुख प्रतिस्पर्धी अमेरिकी कंपनी एमेजॉन के साथ कारोबारी जंग की शुरुआत की थी।

वॉलमार्ट इंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी ब्रेट बिग्स ने कहा, 'चौथी तिमाही की शुरुआत और अंत बिक्री में दमदार वृद्धि के साथ हुआ।' उन्होंने कहा, 'हमने चिली के साथ-साथ कुछ प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बाजारों में नरमी दर्ज की है जहां अशांति के कारण हमारे अधिकतर स्टोरों में उथल-पुथल देखा गया। जबकि वॉलमेक्स (वॉलमार्ट डि मेक्सिको), चीन और फ्लिपकार्ट के लिए यह दमदार तिमाही रही।'

वॉलमार्ट ने कहा कि 31 जनवरी 2020 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए परिसंपत्ति पर रिटर्न बढ़कर 6.7 फीसदी हो गया जो एक साल पहले 3.4 फीसदी रहा था। रिटर्न में वृद्धि की मुख्य वजह चीन की ई-कॉमर्स कंपनी जेडी डॉट कॉम में निवेश के उचित मूल्य में बदलाव के कारण समेकित शुद्ध आय और वॉलमार्ट ब्राजील में बहुलांश हिस्सेदारी से बिक्री से संबंधित वित्त वर्ष 2019 का 4.5 अरब डॉलर का घाटा रही।

वॉलमार्ट को फ्लिपकार्ट से बल

- चौथी तिमाही में वॉलमार्ट इंटरनैशनल के लिए ई-कॉमर्स ने इस श्रेणी की कुल बिक्री में 12 फीसदी का योगदान किया
- कई बाजारों में किराने के सामान की ऑनलाइन बिक्री और फ्लिपकार्ट से मिली रफ्तार
- विश्व के सबसे बड़े खुदरा विक्रेता ने कहा, कोरोनावायरस के कारण वह अपना बिक्री अनुमान नहीं घटाएगी

रेडिसन की नजर छोटे शहरों में विस्तार पर

पवन लाल
मुंबई, 18 फरवरी

बेल्जिम की होटल शृंखला रेडिसन होटल ग्रुप ने अपनी मौजूदगी उस तरह नहीं बढ़ाई जैसा उसने योजना बनाई थी। लेकिन टियर-2 एवं टियर-3 बाजार में मौजूदा होटलों से कंपनी का वृद्धि दिख रही है। कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि कंपनी के होटलों की कुल संख्या में टियर-2 एवं टियर-3 बाजार की हिस्सेदारी आगे चलकर 50 फीसदी होगी।

रेडिसन के प्रबंध निदेशक एवं महाप्रबंधक (परिचालन- दक्षिण एशिया) जुबिन सक्सेना ने कहा कि कंपनी फिलहाल भारत के करीब 60 शहरों में 94 होटलों का परिचालन करती है। इसमें टियर-2 एवं टियर-3 बाजार के होटलों से वृद्धि को रफ्तार मिल रही है। उन होटलों में कमरों का भराव दर और औसत दैनिक दरों में हाल में तेजी आई है। खासतौर पर पिछले तीन साल के दौरान रेडिसन के औसत दैनिक दरों में औसतन 10 फीसदी से करीब 65 फीसदी तक की वृद्धि देखी गई है और वह 3,500 रुपये से बढ़कर करीब 4,500 रुपये हो चुका है। पिछले साल कंपनी ने दो होटल (रेडिसन गुरुग्राम और रेडिसन आगरा) खोले थे और अगले दो वर्षों में आठ नए होटल खोलने की योजना है।

कंपनी नए होटलों के लिए टियर-2 एवं टियर-3 शहरों, राज्यों की राजधानी, तीर्थ स्थल, औद्योगिक क्षेत्र और पर्यटन स्थलों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। साथ ही कंपनी ने घोषणा की है कि उसने भविष्य में 17 नए होटल खोलने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। रेडिसन होटल ग्रुप ने इससे पहले कहा था कि वह 2022 तक होटलों की संख्या को बढ़ाकर 150 से 200 बीच करना चाहती है। एक विश्लेषक ने अपनी पहचान जाहिर न करने की शर्त पर कहा कि दुनिया भर में आर्थिक नरमी और भारत में बढ़ी प्रतिस्पर्धा जैसे तमाम कारकों के मद्देनजर इस लक्ष्य को हासिल करना आसान नहीं दिख रहा है।

सक्सेना ने कहा कि फिलहाल कंपनी सभी 94 होटलों को समान परियोजना प्रबंधन एवं खरीद व्यवस्था के तहत रखा गया है। इससे कंपनी को लागत बचाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, 'इससे पहले हम स्वतंत्र रूप से परिचालन वाले होटल थे लेकिन अब उसमें बदलाव किया गया है।

जेट को मिला एक और अभिरुचि पत्र, सीओसी ने बढ़ाई तारीख

एन्सो ग्रुप और रूस के फार ईस्ट डेवलपमेंट फंड ने संयुक्त रूप से जेट एयरवेज के लिए अभिरुचि पत्र जमा कराया है। एक सूत्र ने यह जानकारी दी। दूसरे दौर की बोली में जेट एयरवेज को यह तीसरा अभिरुचि पत्र मिला है। इस प्रगति के बाद लेनदारों की समिति ने मंगलवार को समाधान योजना जमा कारने की आखिरी तारीख 9 मार्च कर दी। एन्सो ग्रुप और रूसी फंड ने अपना अभिरुचि पत्र कुछ दिन पहले रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल को सौंपा और बोली प्रक्रिया में मदद के लिए उन्होंने एक कंसल्टेंसी फर्म को नियुक्त किया है। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग को भारत-यूरोप और भारत-अमेरिका ट्रैफिक के लिए केंद्र के तौर पर विकसित करने की संभावना तलाशने के लिए यह बोली लगाई गई है। यह फंड रूसी नागरिक विमान मसलन सुखोई सुपरजेट 100 भारतीय बाजार में उतारने की इच्छुक है। एक सूत्र ने यह जानकारी दी। जेट एयरवेज में दिलचस्पी रखने वाली दो अन्य इकाइयां हैं नई दिल्ली की प्रूडेंट एआरसी और दक्षिण अमेरिका का सिनर्जी ग्रुप। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर स्लॉट से संबंधित मुद्दों के कारण सिनर्जी ग्रुप फिलहाल कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा है।

जेट एयरवेज के मुख्य रणनीति अधिकारी राजेश प्रसाद ने कहा, रूसी फंड की दिलचस्पी शानदार प्रगति है। समाधान में चुनौतियां हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि उनका समाधान किया जा सकता है। *बीएस*

जीएफजी अलायंस ने किया अधिग्रहण

ईशिता आयान दत्त
कोलकाता, 18 फरवरी

भारत में जन्मे ब्रिटिश कारोबारी संजीव गुप्ता की अगुआई वाली जीएफजी अलायंस ने मंगलवार को कहा कि 425 करोड़ रुपये के नकद सौदे के जरिये उसने आधुनिक मेटलिक्स लिमिटेड और जिऑन स्टील के रणनीतिक अधिग्रहण का काम पूरा कर लिया और इस तरह से कंपनी भारत में प्रवेश कर गई।

इस अधिग्रहण पर टिप्पणी करते हुए जीएफजी अलायंस के कार्यकारी चेयरमैन गुप्ता ने कहा, आधुनिक मेटलिक्स की खरीद और भारत में प्रवेश से आज हम वैश्विक स्टील रणनीति के अहम पड़ाव पर हैं, जो तेजी से आगे बढ़ने वाले देशों में से एक और दुनिया का सबसे ज्यादा वाइब्रेंट स्टील बाजार है। अपने ग्रीनस्टील मॉडल के जरिए हमें इस कारोबार में काफी संभावना दिख रही है।

आधुनिक के वित्तीय लेनदारों का दावा करीब 5,000 करोड़ रुपये का है। स्टील प्लांट को बहाल करने के लिए जीएफजी अलायंस की योजना ग्रीनस्टील मॉडल लागू करने की है, जिसमें कम कार्बन व अक्षय ऊर्जा स्रोत के जरिये स्टील की रीसाइक्लिंग होगी ताकि स्थानीय बाजार के लिए स्थायी व प्रतिस्पर्धी परिचालन हो सके।

गुप्ता ने कहा, इस चरण तक पहुंचना हमारे लिए चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन अब हम इन संयंत्रों को बहाल करने और रोजगार वापस लाने के लिए सभी हितधारकों के साथ साझेदारी से काम करना चाह रहे हैं। इस देश में निवेश करना काफी अहम है, जहां हमारे परिवार ने एक पीढ़ी पहले स्टील उद्योग की शुरुआत की थी।

आधुनिक के मामले में काफी उतारचढ़ाव देखने को मिले। एनसीएलटी ने उस समय इस कंपनी के परिसमापन का आदेश दिया था जब लिबर्टी अपनी समाधान योजना लागू करने में नाकाम रही। एनसीएलएटी ने हालांकि लिबर्टी की अपील पर परिसमापन आदेश पर रोक लगा दी। लिबर्टी को भुगतान के लिए 14 फरवरी तक का समय दिया गया था। कंपनी ने 13 फरवरी को लेनदेन पूरा कर लिया और सोमवार को अपील ट्रिब्यूनल ने कहा कि अधिग्रहण पूरा करने के लिए औपचारिक कदम उठाए जा सकते हैं।

पिछले दो साल में लिबर्टी समूह ने दिवालिया संहिता के तहत नीलाम हो रही परिसंपत्तियों भूषण पावर ऐंड स्टील, एमटेक ऑटो और एबीजी शिपयार्ड आदि के अधिग्रहण की कई कोशिश की।

एमटेक ऑटो लिबर्टी के हाथ लगी। हालांकि एमटेक की समाधान योजना लागू नहीं हो पाई और दिवालिया प्रक्रिया दोबारा शुरू हुई। एमटेक के लेनदारों ने हाल में अमेरिकी हेज फंड डेक्कन वैल्यू इन्वेस्टर्स एलपी के समाधान योजना के हक में मतदान किया है।

क्विकर का मूल्यांकन घटाया

ऑनलाइन क्लासीफाइड मार्केटप्लेस क्विकर अब 1 अरब डॉलर मूल्यांकन वाले स्टार्टअप की जमात फिसल गई है। अपनी वर्षांत रिपोर्ट में उसके प्रमुख शेयरधारक एवं स्वीडन की निवेश फर्म किनेविक ने क्विकर का मूलयांकन 45 फीसदी घटा दिया है। लेनदेन में धोखाधड़ी के कारण राजस्व को बढ़ाचढ़ाकर पेश किए जाने का उल्लेख करते हुए किनेविक ने मूल्यांकन में कटौती की है। क्विकर का मूल्यांकन अब करीब 57.7 करोड़ डॉलर है।

किनेविक ने इसी महीने अपनी एक प्रस्तुति में कहा, 'क्विकर में हमारे निवेश का उचित मूल्यांकन करीब 45 फीसदी घटकर 76.4 करोड़ क्रोना रह गया है। इससे धोखाधड़ी वाले लेनदेन के साथ-साथ उसकी घटती मौजूदगी और संशोधित राजस्व मान्यता सिद्धांतों की झलक मिलती है।' *बीएस*

बीएस बातचीत

व्यापक बाजार के लिए लेकर आएंगे इलेक्ट्रिक वाहनः पवन मुंजाल

हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन **पवन मुंजाल** को दिसंबर 2010 में जापान की कंपनी होंडा मोटर के साथ गठजोड़ टूटने के बाद से ही लगातार सवालों के जवाब देने पड़े हैं। वह दोपहिया बाजार में अपनी हिस्सेदारी बरकरार रखने के साथ ही अधिकतर आलोचकों को शांत करने में सफल रहे हैं। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर बढ़ी सक्रियता के बीच मुंजाल ने अपनी भावी योजनाओं को लेकर **अरिंदम मजूमदार** से बातचीत की। पेश हैं संपादित अंशः

क्या भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए तैयार है?

इस दिशा में कदम बढ़ाया जा चुका है। हालांकि इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी के एक स्तर तक पहुंचने में कुछ साल लगेंगे। वाहन उद्योग को 2025 तक इलेक्ट्रिक वाहनों को अहमियत देने को कहा जा रहा था। वाहन उद्योग ऐसा कर भी सकता है लेकिन इसका ढांचा क्या होगा? सवाल अकेले उद्योग जगत का ही नहीं है। वाहन कलपुर्जा उद्योग के लिए यह काम अधिक मुश्किल है। इसके लिए कौशल विकसित करना होगा। ऐसी बीस चीजें हैं जिन्हें एक साथ करने की जरूरत है।

आपके अनुभव के हिसाब से इस बाजार के परिपक्व होने में कितना वक्त लगेगा?

फिलहाल इलेक्ट्रिक वाहन के मामले में हमारा कोई अनुभव नहीं है। ऐसे में मैं कोई समयसीमा नहीं रखना चाहता।

आपके प्रतिद्वंद्वियों बजाज और टीवीएस ने वाहन बाजार के उच्च स्तर पर कुछ इलेक्ट्रिक वाहन उतार दिए हैं। इस बारे में हीरो की क्या योजना है?

वर्ष 2012 में सरकार की तरफ से कोई दबाव नहीं था लेकिन हमने एक हाइब्रिड स्कूटर पर काम शुरू कर दिया था। इसके अलावा हमने एथर एनर्जी में काफी पैसे भी लगाए। इस कंपनी की 35 फीसदी हिस्सेदारी लेना कोई छोटा कदम नहीं था। हम इलेक्ट्रिक वाहनों के शोध एवं विकास और इंक्यूबेशन दोनों पर ही काम कर रहे हैं। वैसे हम किसी तरह की जल्दबाजी में नहीं हैं। हम एक ऐसा इलेक्ट्रिक वाहन लेकर आएंगे जिसे बाजार का बड़ा तबका स्वीकार करेगा और हमारी बिक्री बढ़ेगी। एक लाख रुपये की कीमत वाले वाहन से हमें कितनी बिक्री मिल पाएगी? एक कंपनी के तौर पर हम किसी भी सेगमेंट से बंधकर नहीं रहेंगे। भविष्य में हमारे पास एक बड़ा पोर्टफोलियो होगा लेकिन फिलहाल ई-वाहन का सेगमेंट बेहद खास होने से हम व्यापक बाजार के लिए उत्पाद पर ध्यान दे रहे हैं।

आपने एथर एनर्जी में बड़ा निवेश किया है। क्या इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में एथर ही हीरो के लिए प्लेटफॉर्म बनेगी?

इस कंपनी में निवेश के जरिये हम पहले से ही वहां मौजूद हैं। भले ही यह हीरो ब्रांड न हो लेकिन इसे हीरो का समर्थन और पैसा हासिल है। हम बड़े बाजार के लिए उत्पाद लाने पर काम कर रहे हैं लेकिन एथर कोई व्यापक बाजार वाला उत्पाद न होकर प्रीमियम श्रेणी का है। यानी हम दोनों का सफर अलग है।

हीरो एक मॉड्यूलर मोबिलिटी संकल्पना पर काम कर रही है। क्या आप इस मॉडल को वाणिज्यिक स्तर पर लाने की योजना बना रहे हैं?

हमने अभी तक मॉड्यूलर मोबिलिटी संकल्पना के वाणिज्यिक उत्पादन के बारे में नहीं सोचा है। अभी यह बहुत शुरुआती दौर में है। हमारी एक नवोन्मेष टीम ने इसका विचार रखा था और हमें भी इसमें चमकदार भविष्य नजर आ रहा है। हमें इस प्रोजेक्ट पर अभी काफी काम करना है।

क्या आप वाहन जगत के स्टार्टअप को व्यक्तिगत मार्गदर्शन देंगे?

मैं स्टार्टअप में निवेश करता रहा हूं जिनमें मोबिलिटी जगत के स्टार्टअप भी शामिल हैं। लेकिन इस बात का कंपनी से कोई लेना-देना नहीं है।

एक कंपनी के तौर पर आपने शोध एवं विकास में 10,000 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की है। क्या इसमें वैकल्पिक आवागमन साधन से जुड़े समाधान भी शामिल हैं?

हमारे इंजीनियर तमाम परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। इन परियोजनाओं में ई-वाहन जैसे वैकल्पिक आवागमन साधन भी शामिल हैं।

क्या दोपहिया श्रेणी में सवारी-साझेदारी की संकल्पना रफ्तार पकड़ पाएगी?

हां, ऐसा होगा। लेकिन इसका वक्त बता पाना अभी काफी मुश्किल है। वैसे अब पीछे लौटने का सवाल ही नहीं है- चाहे वह इलेक्ट्रिक हो या सवारी-साझेदारी। इसी वजह से हम इस पर जोर दे रहे हैं।

क्या आप सवारी-साझेदारी श्रेणी को साधने के लिए अलग उत्पाद लेकर आएंगे?

हमें इसका मूल्यांकन करने की जरूरत है। अलग श्रेणी के उत्पादों की जरूरत शायद न हो लेकिन उनके संस्करण की जरूरत हो सकती है।

क्या आप भावी सफर के लिए रणनीतिक साझेदारी करना चाहेंगे?

हम हरेक तरह की साझेदारी के लिए तैयार हैं चाहे वह ई-वाहन हो या तकनीक या फिर सवारी-साझेदारी का सवाल हो। जब भी एक बढ़िया विकल्प मिलेगा, हम निश्चित रूप से उसके बारे में सोचेंगे।

कीमत पर दबाव से 15 साल के निचले स्तर पर ओएनजीसी

घटते कारोबार व कम कीमत से तीसरी तिमाही रही कमजोर। सरकारी हिस्सा बेचने की योजना का निवेशकों की धारणा पर पहले से ही असर है

उज्ज्वल जौहरी
मुंबई, 18 फरवरी

ओएनजीसी का शेयर मंगलवार को टूटकर 15 साल के निचले स्तर पर आ गया। यह शेयर पहले ही पिछले साल मई के उच्चस्तर से 44 फीसदी टूट चुका है। कोरोनावायरस के प्रसार के कारण कच्चे तेल की मांग घटने की चिंता और इसके कारण तेल की कीमतों में गिरावट ने बाजार की धारणा को कमजोर कर दिया, जो इस कंपनी की तीसरी तिमाही के सुस्त नतीजे के बाद नरम रुख अपनाए हुए थे।

दिसंबर तिमाही में ओएनजीसी का एकल राजस्व 14 फीसदी घटा जबकि शुद्ध लाभ सालाना आधार पर घटकर करीब आधा रह गया। इसकी वजह कच्चे तेल व गैस की कमजोर कीमतें थी। नामांकित तेल ब्लॉक से मिलने वाली रकम 59.73 डॉलर प्रति बैरल रही, जो सालाना आधार पर 10 फीसदी कम है। बुरी बात यह रही कि ब्रेंट की औसत कीमत तीसरी तिमाही में 62.5 डॉलर प्रति बैरल रही, लेकिन अब यह घटकर 56.5 डॉलर प्रति बैरल रह गई है। और इन चीजों ने कंपनी की आय को लेकर चिंता बढ़ा दी है।

शेयर पर चोट

- यह शेयर पहले ही पिछले साल मई के उच्चस्तर से 44 फीसदी टूट चुका है
- दिसंबर तिमाही में ओएनजीसी का एकल राजस्व 14 फीसदी घटा जबकि शुद्ध लाभ सालाना आधार पर घटकर करीब आधा रह गया

बिक्री से मिलने वाली रकम पर दबाव ऐसे समय में देखा गया जब कंपनी का तेल व गैस का उत्पादन भी निवेशकों को उत्साहित नहीं कर पाया। कंपनी के कच्चे तेल का उत्पादन क्रमिक आधार पर तीसरी तिमाही में एक फीसदी घटा, लेकिन वित्त वर्ष 2020 के पहले नौ महीने में यह 3 फीसदी कम है। कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने की कंपनी की कोशिश का पिछले कुछ साल से बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिला है। विश्लेषकों ने कहा कि उत्पादन का बड़ा हिस्सा पुराने क्षेत्रों से आ रहा है जबकि नया क्षेत्र उसकी भरपाई करने में सक्षम नहीं हो पाया है।

सहारे के लिए बाजार गैस उत्पादन में बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहा था। हालांकि यहां भी उम्मीदें पूरी नहीं हुई। कंपनी का गैस उत्पादन तीसरी तिमाही में सालना आधार पर 8.4 फीसदी घटा, जो कई तिमाहियों में सबसे तेज गिरावट है। इस गिरावट की वजह असम का अवरोध है, लेकिन वित्त वर्ष के पहले नौ महीने में भी गैस उत्पादन 2.6 फीसदी घटा है। बाजार की धारणा में सुधार के लिए गैस उत्पादन में बढ़ोतरी अहम है क्योंकि गैस की कीमतें नरम बनी हुई है। सकल कैलोरिफिक वैल्यू के आधार पर दिसंबर तिमाही में गैस की कीमतें सालाना आधार पर 3.9 फीसदी घटकर 3.23 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू रही।

सेंट्रम ब्रोकिंग के विश्लेषकों ने दिसंबर तिमाही के नतीजे के बाद कहा था कि तेल का उत्पादन लगातार 9 तिमाहियों से घट रहा है और गैस का उत्पादन भी पिछली दो तिमाहियों में घटा है, ऐसे में परिचालन के स्तर पर प्रदर्शन अगले 12-15 महीने में सुस्त रह सकता है। कंपनी के दिशानिर्देश और ताजा अनुमान के मुताबिक वित्त वर्ष 2022 से पहले इसमें सुधार नहीं होगा। सरकारी हिस्सेदारी की बिक्री होने से भी ओएनजीसी जैसे पीएसयू शेयरों पर दबाव बना हुआ है। शेयरखान के अभिजित बोरा ने कहा, तीसरी तिमाही में कमजोर प्रदर्शन के कारण ओएनजीसी के शेयरों की कीमतें तेजी से घटी हैं। साथ ही तेल व गैस की बिक्री से कम रकम मिलने और सरकारी हिस्सेदारी बिक्री न होने का भी इस पर असर पड़ा है। अगर तेल की कीमतों पर दबाव बना रहा तो ओएनजीसी के शेयरों में आगे भी गिरावट जारी रहेगी।

4 साल के निचले स्तर पर निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स

सार्वजनिक क्षेत्र के आठ बैंकों के शेयर टूटकर करीब 10 साल के निचले स्तर पर

दीपक कोरगांवकर और पुनीत वाधवा
मुंबई/नई दिल्ली, 18 फरवरी

सार्वजनिक बैंकों के शेयरों पर मंगलवार को भी दबाव बना रहा और निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स चार साल के निचले स्तर पर आ गए। कारोबारी सत्र के दौरान यह इंडेक्स 2,074.55 अंक के निचले स्तर को छू गए, जो 1 मार्च 2016 के बाद का निचला स्तर है क्योंकि तब कारोबारी सत्र में यह इंडेक्स 2,053.60 अंक के निचले स्तर को छू गया था। यह इंडेक्स 9 अक्टूबर 2019 के निचले स्तर 2113.05 अंक से भी नीचे चला गया। पिछले तीन कारोबारी सत्र में निफ्टी पीएसयू इंडेक्स 6 फीसदी टूटा है जबकि बेंचमार्क इंडेक्स में 1.5 फीसदी की गिरावट आई है।

बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नैशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, सिंडिकेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, आन्ध्रा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया के शेयर एनएसई पर 10 साल के निचले स्तर को छू गए। इसके अलावा इंडियन बैंक और केनरा बैंक के शेयर चार साल के निचले स्तर को छू गए।

यह गिरावट कमजोर आर्थिक प्रवृत्ति के बीच हुई है जो उधारी की रफ्तार में कमी ला सकता है और अल्पावधि में फंसे कर्ज में बढ़ोतरी जारी रह सकती है। इसके अलावा दूरसंचार क्षेत्र के संकट ने चिंता और बढ़ा दी है। हाल में सर्वोच्च न्यायालय ने दूरसंचार कंपनियों से एजीआर बकाया न वसूलने पर दूरसंचार विभाग को फटकार लगाई है।

मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज के मुताबिक, एजीआर की देनदारी पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता पर असर पड़ेगा और वित्त वर्ष 2021 में उधारी की लागत बढ़ सकता है, खास तौर से ऐसे समय में जब वोडाफोन आइडिया के बंद होने का जोखिम है। मोतीलाल ओसवाल के संस्थागत शोध प्रमुख गौतम दुग्गड़ ने कहा, बाकी बैंकों के मुकाबले भारतीय स्टेट बैंक के पास दबाव वाली दूरसंचार कंपनियों के लिए ज्यादा प्रावधान की क्षमता है क्योंकि दबाव वाले अन्य खाते और कार्ड बिजनेस के विनिवेश के कारण उसके पास ज्यादा रकम होगी।

एमके ग्लोबल के विश्लेषक की राय भी ऐसी ही है। एजीआर बकाया पर न्यायालय के फैसले ने पहले ही एसबीआई, इंडसइंड बैंक, येस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ऐक्सिस बैंक, पीएनबी आदि के लिए वोडा-आइडिया के डिफॉल्ट का जोखिम बढ़ा दिया है।

इस बीच, एसबीआईकैप के विश्लेषकों ने कहा है, दिवालिया संहिता के तहत दिवालिया समाधान अभी गति नहीं पकड़ पाया है, जैसा कि आईबीबीआई की तीसरी तिमाही के पब्लिकेशन में संकेत दिया गया है।

एमके ग्लोबल के विश्लेषकों ने हाल में कहा है, एनसीएटी या गैर-एनसीएलटी के जरिये रतन इंडिया नासिक, जिंदल थर्मल, आरकेएम पावर, एस्सार ट्रांसमिशन, इंडिया पावर हल्दिया, जल पावर, झाबुआ पावर, इंड भारत उत्कल, केएसके महानदी, जीएमआर कमलांगा आदि के कॉरपोरेट दिवालिया समाधान की संभावना बढ़ रही है। बैंकों को अगली दो तिमाहियों में भूषण पावर समेत इन कंपनियों से रकम मिलने की उम्मीद है, जिससे आने वाले समय में एनपीए कम होगा।

सार्वजनिक बैंकों के शेयर

बैंक	31 दिसंबर 2019	18 फरवरी 2020	बदलाव (फीसदी)
इलाहाबाद बैंक	18.80	14.00	-25.53
सिंडिकेट बैंक	27.80	21.70	-21.94
केनरा बैंक	221.30	172.90	-21.87
पंजाब ऐंड सिंध बैंक	21.10	16.65	-21.09
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	54.80	43.30	-20.99
बैंक ऑफ बड़ौदा	101.90	81.05	-20.46
इंडियन बैंक	100.85	80.25	-20.43
ओबीसी	52.05	41.80	-19.69
पीएनबी	64.35	52.05	-19.11
इंडियन ओवरसीज बैंक	11.25	9.10	-19.11
निफ्टी पीएसयू बैंक	2,524.35	2,128.20	-15.69
निफ्टी-50	12,168.45	11,992.50	-1.45

स्रोत : एक्सचेंज। शेयरों की कीमतें रुपये में। संकलन : बीएस रिसर्च ब्यूरो

बारबेक्यू नेशन ने जमा कराया आईपीओ दस्तावेज

अर्णव दत्ता
नई दिल्ली, 18 फरवरी

भारतीय रेस्तरां शृंखला बारबेक्यू नैशनल हॉस्पिटिलिटी ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम के लिए दस्तावेज जमा कराया है। बेंगलूरु की यह फर्म देश के 78 शहरों में 138 आउटलेट्स का परिचालन करती है और आईपीओ के जरिए अनुमानित तौर पर 1,000 से 1,250 करोड़ रुपये जुटाने जा रही है।

चेन्नई की सयाजी हाउसकीपिंग सर्विसेज और इक्विटी फर्म सीएक्स पार्टनर्स के प्रवर्तन वाली यह कंपनी 98.2 करोड़ शेयरों की पेशकश करेगी, जिसमें 275 करोड़ रुपये के नए शेयर होंगे। फर्म ने आईपीओ दस्तावेज में ये बातें कही है। 50 फीसदी शेयर पात्र संस्थागत निवेशकों के लिए होंगे जबकि 35 फीसदी व 15 फीसदी क्रमशः खुदरा निवेशकों और गैर-संस्थागत बोलीदाताओं के लिए होंगे।

प्रमुख मालिकों सयाजी हाउसकीपिंग सर्विसेज और इक्विटी फर्म सीएक्स पार्टनर्स की हिस्सेदारी क्रमशः 45.09 फीसदी व 21.71 फीसदी है जबकि पेस प्राइवेट लिमिटेड के पास 11.37 फीसदी, कुयुम धनानी के पास 4.64 फीसदी और राकेश झुनझुनवाला की अल्केमी इंडिया के पास 2.05 फीसदी हिस्सेदारी है। यही निवेशक अपने शेयरों की बिक्री की पेशकश करेंगे। आईआईएफएल सिक्योरिटीज, ऐक्सिस कैपिटल और एसबीआई कैपिटल इस आईपीओ की बुक रनिंग लीड मैनेजर है। आईपीओ से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल कंपनी कर्ज घटाने और कंपनी के सामान्य कामकाज पर करेगी। कंपनी का एकीकृत कर्ज 225 करोड़ रुपये है। कंपनी का शेयर बीएसई व एनएसई पर सूचीबद्ध कराया जाएगा।

परिसंपत्ति गुणवत्ता पर इंडसइंड बैंक को राहत नहीं

दूरसंचार क्षेत्र को दी गई उधारी पर बैंक के स्पष्टीकरण के बावजूद शेयर कीमतों पर इसका बहुत असर नहीं पड़ा

हंसिनी कार्तिक
मुंबई, 18 फरवरी

इंडसइंड बैंक का शेयर मंगलवार को तीन साल के निचले स्तर को छू गया, जब वह दो फीसदी से ज्यादा टूटकर 1,140 रुपये पर बंद हुआ। ब्लूमबर्ग की रायशुमारी में 70 फीसदी से ज्यादा विश्लेषक औसत लक्षित कीमत 1,676 रुपये को लेकर सकारात्मक हैं, लेकिन बाजार में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा क्योंकि निजी क्षेत्र के बैंकों में इंडसइंड बैंक का शेयर कैलेंडर वर्ष 2020 में 24 फीसदी की सबसे बड़ी गिरावट देख चुका है।

खास तौर से दूरसंचार कंपनियों को दी गई उधारी पर अनिश्चितता को देखते हुए इसके प्रति सकारात्मक बने रहने की बाध्यता धीरे-धीरे खत्म हो रही है। यही वजह है कि आखिर बैंक दूरसंचार क्षेत्र को दी गई उधारी पर स्पष्टीकरण क्यों दे रहा है, जबकि इस मोर्चे पर वह बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया है। साथ ही दूरसंचार क्षेत्र में उसकी उधारी कुल लोनबुक के 1.2 फीसदी तक सीमित है और वोडाफोन को फंड आधारित 995 करोड़ रुपये की उधारी दी गई है जबकि गैर-फंड आधारित उधारी 2,409 करोड़ रुपये की है। ऐसे में चिंता इस बात की है कि क्या इंडसइंड बैंक परिसंपत्ति गुणवत्ता पर एक बार फिर दबाव झेल पाएगा।

आईएलऐंडएफएस और हाउसिंग फाइनैंस कंपनियों से संबंधित फंसे कर्ज का दबाव बैंक पर पड़ रहा है और उसकी गैर-निष्पादित आस्तियों का अनुपात दिसंबर तिमाही में कई तिमाहियों के उच्चस्तर 2.2 फीसदी को छू गया। मैक्वेरी कैपिटल के सुरेश गणपति के अनुमान

के मुताबिक, दबाव वाले तीन प्रमुख क्षेत्रों रियल एस्टेट (लीज रेंटल समेत), दूरसंचार और जेम्स ऐंड ज्वैलरी में कुल उधारी लोनबुक का करीब 13 फीसदी है। उन्होंने कहा, इसके अतिरिक्त माइक्रोफाइनैंस (लोनबुक का 10 फीसदी) और वाणिज्यिक वाहनों (16 फीसदी) कर्ज को लेकर भी चिंता है। अगर हम वाणिज्यिक वाहनों पर कर्ज के दबाव को साइक्लिकल मानें तो अन्य क्षेत्रों के कर्ज का निपटारा कैसे होता है, उस पर नजर रहेगी।

बड़ी चिंता शायद परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार को लेकर है। तीसरी तिमाही के नतीजे के दौरान प्रबंधन ने वित्त वर्ष 2021 में परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार का संकेत दिया था। हालांकि मॉर्गन स्टैनली का अनुमान है कि कुल कर्ज के प्रतिशत के तौर पर सकल एनपीए वित्त वर्ष 2022 में 3.7 फीसदी को छू जाएगा, जो तीसरी तिमाही में 2.2 फीसदी था। ब्रोकरेज ने पहले कहा था कि वित्त वर्ष 2022 में सकल एनपीए अनुपात 2.4 फीसदी रहने का अनुमान है।

रमेश सोबती के उत्तराधिकारी के खुलासे पर बैंक की चुप्पी से भी बाजार आशंकित है, जो 23 मार्च को बैंक के प्रबंध निदेशक व सीईओ का पद छोड़ रहे हैं।

एवरेडी इंडस्ट्रीज में डाबर के बर्मन ने ली हिस्सेदारी

अभिषेक रक्षित और ईशिता आयान दत्त
कोलकाता, 18 फरवरी

एक ओर जहां विलियमसन मेगॉर ग्रुप (डब्ल्यूएमजी) के स्वामित्व वाली एवरेडी इंडस्ट्रीज समूह के स्तर पर वित्तीय संकट का सामना कर रही है, वहीं दूसरी ओर डाबर की बर्मन फैमिली ने एवरेडी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 5.01 कर दी है।

पिछले चार महीने में गार्डियन एडवाइजर्स धीरे-धीरे अपनी शेयरधारिता बढ़ा रहा है। अर्जुन लांबा और अन्य के स्वामित्व वाली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फर्म अन्य परिवारों के अलावा बर्मन के लिए निवेश का प्रबंधन करती है। सूत्रों ने कहा कि एवरेडी में यह निवेश बर्मन फैमिली के लिए किया गया है। इस महीने नियामकीय सूचना में गार्डियन एडवाइजर्स ने कहा कि एवरेडी में यह निवेश अपने क्लाइंटों के बदले किया गया है और इक्विटी हिस्सेदारी का स्वामित्व निवेशक के पास है, वहीं गार्डियन एडवाइजर्स के पास एवरेडी में किए गए निवेश के प्रबंधन के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी है।

डाबर इंडिया के वाइस चेयरमैन मोहित बर्मन ने कहा, मेरा मानना है कि एवरेडी मजबूत ब्रांड और अपने क्षेत्र में बाजार की अग्रणी भी है, ऐसे में हमने इस कंपनी की हिस्सेदारी ली है।

व्यक्तिगत निवेश क्षमता के जरिए कई उच्च बढ़त वाले व आगे बढ़ने वाले क्षेत्रों में बर्मन फैमिली के उतरने के पीछे बर्मन का बड़ा हाथ रहा है। समूह के वित्तीय सेवा कारोबार को परिसंपत्ति प्रबंधन, ब्रिटेन की बीमा कंपनी अवीवा के साथ अवीवा लाइफ इंश्योरेंस इंडिया की स्थापना के जरिये विस्तार देने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है।

विगत में वह पंजाब ट्रैक्टर्स लिमिटेड की 14 फीसदी हिस्सेदारी लेकर एक अन्य उद्योग में कदम रखा है और डाबर की तरफ से बलसारा के हम व हाइजिन बिजनेस के अधिग्रहण में भी अहम रहे हैं।

डब्ल्यूएमजी व एवरेडी में दबाव के समय निवेश के बारे में पूछे जाने पर बर्मन ने कहा, समूह मुश्किल दौर से गुजर रहा है और शेयर कीमत पर भी यह प्रतिबिंबित हुआ है। लेकिन कंपनी का ब्रांड व उसका प्रमुख कारोबार बना हुआ है।

समूह कंपनियों को अंतर-कंपनी जमाओं और उसके पुनर्भुगतान को लेकर अनिश्चिताओं के कारण एवरेडी के शेयर पर काफी चोट पड़ी है। 18 फरवरी 2018 को एवरेडी का शेयर 394 रुपये का था, जो पिछले साल 15 अक्टूबर को करीब 38 रुपये का रह गया था और उसके बाद से इसमें सुधार हो रहा है। यह शेयर अभी 65-66 रुपये पर है। सूत्रों ने कहा, रकम जुटाने की आवश्यकता के समय एवरेडी बर्मन फैमिली से संपर्क पर विचार कर सकती है।

संक्षेप में

जलाशय क्षेत्र में 2.8 लाख मेगावॉट सौर ऊर्जा क्षमता

देश में 18,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले जलाशयों में सौर परियोजनाएं लगाकर 2,80,000 मेगावॉट सौर ऊर्जा उत्पादन किया जा सकता है। एनर्जी ट्रांसमिशन कमीशन (ईटीसी) के तहत द एनर्जी एंड रिर्सोसेस इंस्टीट्यूट (टेरी) की तरफ से जारी रिपोर्ट में यह बात कही गई है। यह रिपोर्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टेक (एफएसपीवी): ए थर्ड पिलर टू सोलर पीवी सेक्टर शीर्षक से जारी की गई। टेरी की इस नई रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में जलाशय 18,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं। इसमें फ्लोटिंग सौर संयंत्रों से 2,80,000 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता है। *भाषा*

जलवायु परिवर्तन क्षेत्र के लिए बेजोस का कोष

ई-वाणिज्य कंपनी एमेजॉन के मुख्य कार्याधिकारी जेफ बेजोस ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 10 अरब डॉलर का कोष बनाने की प्रतिबद्धता जताई है। बेजोस ने सोमवार को इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में लिखा कि बेजोस अर्थ फंड उन सभी वैज्ञानिकों, कार्यकर्ताओं और गैर-सरकारी संगठनों के उन सभी कामों के लिए मदद उपलब्ध कराएगा जिनमें प्रकृति और विश्व की सुरक्षा की वास्तविक संभावना है। *भाषा*

खर्च में कटौती करें बीमाकर्ता : खुंटिया

सुब्रत पांडा
मुंबई, 18 फरवरी

भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के चेयरमैन सुभाष चंद्र खुंटिया ने कहा है कि सामान्य बीमा कंपनियों को कीमतों में बढ़ोतरी पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय बट्टे खाते के घाटे से बाहर निकलने के लिए अपने खर्च में कटौती करने, कार्यकुशलता में सुधार करने और बेहतर उत्पाद की डिजाइन करने पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है।

ज्यादातर सामान्य बीमा कंपनियां बट्टे खाते का घाटा दिखा रही हैं और अपना कारोबार चलाने के लिए धन का प्रबंधन आमदनी के अन्य स्रोतों और निवेश से होने वाली आमदनी से कर रही हैं।

इंस्टीट्यूट आफ एक्चुअरीज आफ इंडिया की ओर से आयोजित 21वें ग्लोबल कॉन्फ्रेंस आफ एक्चुअरीज में खुंटिया ने कहा, 'यह अल्पकालिक कदम है और हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि बट्टे खाते का कोई घाटा न हो। इसका मतलब यह नहीं है कि बीमाकर्ता कीमतें बढ़ा दें, कार्यकुशलता में सुधार करके भी बट्टे खाते का घाटा कम किया जा सकता है। इसी तरह से कंपनी के खर्च पर नियंत्रण किया जा सकता है।'

लेकिन खुंटिया ने कहा कि बीमा नियामक इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा कि बीमाकर्ता अपने उत्पाद की कीमत कैसे तय करते हैं। बहरहाल अगर उन्हें लगता है कि कीमत सही नहीं है तो उत्पाद को मंजूरी देते समय नियामक इस मसले को बीमाकर्ता के सामने रखेगा। खुंटिया ने कहा, 'यह एक खुला बाजार है और हम विनियंत्रण वाली अर्थव्यवस्था में कीमतों का नियमन नहीं चाहते हैं।'

चेयरमैन ने बीमकर्ताओं से यह भी अनुरोध किया कि उन्हें अपने उत्पादों की सालाना समीक्षा करने की जरूरत है, जिससे उन उत्पादों को हटाया जा सकेगा, जिन्हें ग्राहकों ने स्वीकार नहीं किया है। खुंटिया ने कहा, 'सामान्यतया बीमा कंपनियों के 3-4 प्रमुख उत्पादों की उनके कुल कारोबार में अंशदान 80 प्रतिशत होता है। ऐसे में क्या यह जरूरी है कि बड़ी संख्या में जटिल उत्पादों को बनाए रखा जाए, जो ग्राहकों को भ्रमित करते हैं और बीमाकर्ताओं के प्रदर्शन को भी खराब करते हैं?'

आईसीआईसीआई लोंबार्ड जनरल इंश्योरेंस के एमटी और सीईओ भार्गव दासगुप्ता के मुताबिक पहली समस्या तब होती है जब बीमाकर्ता ग्राहकों को सेवा की डिलिवरी देने में पर्याप्त अंडरराइटिंग मुनाफा नहीं रखता है। इससे उद्योग के बारे में नकारात्मक धारणा बनती है और इसकी छवि खराब होती है। दूसरे अगर कंपनियां पर्याप्त धन नहीं रखती हैं तो वे लोगों, वितरण, तकनीक आदि पर खर्च नहीं कर पातीं। तीसरे, कंपनियां नए और नवोन्मेषी उत्पाद नहीं तैयार करतीं। वित्त वर्ष 2020 में सामान्य बीमा उद्योग के कारोबार में 14 प्रतिशत वृद्धि हुई है, जबकि जीवन बीमा क्षेत्र की वृद्धि दर 10 प्रतिशत रही है। लेकिन आईआरडीएआई के चेयरमैन का मानना है कि सामानन्य व जीवन बीमा दोनों क्षेत्र में तेज बढ़ोतरी की संभावना है। खुंटिया ने जीवन बीमाकर्ताओं को अपने दृढ़ता अनुपात में सुधार करने पर ज्यादा ध्यान देने की सलाह दी।

एलआईसी के आईपीओ के बारे में खुंटिया ने कहा कि एलआईसी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश का प्रस्ताव अभी बीमा नियामक के पास मंजूरी के लिए नहीं आया है।

नियामक ने दिए सुझाव

खुंटिया ने कहा कि विनियंत्रण के दौर में मूल्य तय करने का नियामक का इरादा नहीं

14 प्रतिशत सामान्य बीमा के कारोबार में वित्त वर्ष2020 में बढ़ोतरी

10 प्रतिशत जीवन बीमा कारोबार में वृद्धि

- आईआरडीएआई के प्रमुख के अनुसार इस क्षेत्र में बहुत तेज वृद्धि की संभावना
- कंपनियां पॉलिसी को ग्राहकों के मुफीद बनाएं, दाम बढ़ाने पर न हो जोर

बजट प्रबंधन कानून दोबारा लिखने की जरूरत : मोंटेक

भाषा
भोपाल, 18 फरवरी

योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने राज्यों की बढ़ती वित्त जरूरतों और वित्तीय सीमाओं के मद्देनजर मंगलवार को वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन कानून को नए संदर्भों में दोबारा लिखने की जरूरत बताई है।

उन्होंने कहा कि सामाजिक रूप से महत्त्वपूर्ण आर्थिक अधोसंरचना परियोजनाओं में बजट की कमी को दूर करने के लिए निजी-सार्वजनिक भागीदारी का कानून बनाने पर भी विचार करना चाहिए। वह यहां मिंटो हाल में परियोजनाओं के लिए वैकल्पिक वित्त व्यवस्था विषय पर राज्य के वित्त विभाग द्वारा आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा, 'ऐसी स्थिति में निजी क्षेत्र की ओर देखना पड़ता है। निजी क्षेत्र किसी भी प्रकार का खतरा उठाने से बचता है जबकि सरकार हानि-लाभ से परे जन-कल्याण के उद्देश्य के लिए समर्पित होती है। दोनों क्षेत्रों की अपनी सीमाएं हैं। इसलिए दोनों क्षेत्रों के परस्पर सहयोग से काम करने के लिए एक उचित कानून की जरूरत नजर आती है। इस स्थिति से निपटने में वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन कानून पूरी तरह से मददगार साबित नहीं हो पा रहा है।'

अहलूवालिया ने कहा कि परियोजनाएं बनाना, उनके लिए बजट प्रावधान करना और समय रहते उन्हें उपलब्ध संसाधनों में पूरा करना पूरे विश्व में एक मान्य प्रक्रिया है। यह भी तथ्य है कि सरकारों के वित्तीय संसाधन सीमित हैं लेकिन परियोजनाएं महत्त्वाकांक्षी हैं। उन्होंने कहा कि सरकारों के पास सिर्फ आर्थिक अधोसंरचना परियोजनाओं के अलावा भी सामाजिक जिम्मेदारियों के कई काम और प्राथमिकताएं होती हैं। दोनों काम एक साथ पूरा होने में कई चुनौतियां सामने आती हैं। फलस्वरूप योजनाओं और परियोजनाओं की गति धीमी होकर वे पिछड़ने लगती है।

अहलूवालिया ने कहा, 'सिर्फ बजट संसाधनों पर निर्भर रहने की परंपरा से हटकर सोचने की जरूरत है।'

घाटे के लक्ष्य पर आशंका नहीं

भाषा
नई दिल्ली, 18 फरवरी

> सरकार अगले वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा कम कर सकल घरेलू उत्पाद के **3.5** प्रतिशत पर लाने में कामयाब होगी और इसको लेकर कोई संदेह नहीं है

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि सरकार अगले वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा कम कर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 3.5 प्रतिशत पर लाने में कामयाब होगी और इसको लेकर कोई संदेह नहीं है। दास ने कहा कि सरकार घाटे को लेकर राजकोषीय जवाबदेही और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) समिति द्वारा तय सीमा के भीतर है।

मोदी सरकार लगातार तीसरे साल राजकोषीय घाटे का लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी। चालू वित्त वर्ष में इसके बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 3.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है जबकि पूर्व में इसके 3.3 प्रतिशत रहने की संभावना जताई गई थी। अगले वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा 3.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा सरकार के आय और व्यय के अंतर को बताता है। इसका मतलब है कि सरकार के पास जो साधन है, वह उससे अधिक खर्च कर रही है।

दास ने कहा, 'सरकार एफआरबीएम समिति की सिफारिशों के दायरे में है, इसीलिए राजकोषीय घाटा लक्ष्य से केवल 0.5 प्रतिशत ही अधिक हुआ। सरकार इस पर कायम है और अगले साल राजकोषीय घाटे का बड़ा हिस्सा लघु बचत से आएगा।'

एनके सिंह की अध्यक्षता वाली एफआरबीएम समिति ने 2020-21 तक राजकोषीय घाटे को कम कर 2.8 प्रतिशत और 2022-23 तक 2.5 प्रतिशत पर लाने की सिफारिश की है। समिति ने छूट उपबंध का भी सुझाव दिया था। इसके तहत राष्ट्रीय सुरक्षा, युद्ध की स्थिति, राष्ट्रीय आपदा और कृषि के गंभीर रूप से प्रभावित होने के कारण उत्पादन तथा आय पर असर पड़ने की स्थिति में इस प्रावधान का उपयोग किया जा सकता है। इसके तहत राजकोषीय घाटा लक्ष्य से 0.5 प्रतिशत तक अधिक रह सकता है।

दास ने कहा कि अगले साल का राजकोषीय घाटे का लक्ष्य हासिल किया जाएगा और इसमें संदेह का कोई कारण नहीं है। गवर्नर ने कहा कि 2020-21 के बजट में कुछ बांड को बिना किसी सीमा के प्रवासी भारतीयों के निवेश के लिए खोला जाएगा। उन्होंने कहा, 'इसके अलावा कंपनी बांड की सीमा 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत की गई, अत: विदेश से धन भारत आने जा रहा है। भारतीय कंपनियां भी विदेशी बाजारों (ईसीबी) के जरिए विदेशी स्रोत से काफी धन जुटा रही हैं।' दास ने कहा कि कर्ज प्रबंधक के रूप में आरबीआई सुनिश्चित करेगा कि जो उधारी कार्यक्रम है, उसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो।

'विवाद से विश्वास' की शंकाओं का समाधान

इंदिवजल धस्माना
नई दिल्ली, 18 फरवरी

सरकार ने विवाद से विश्वास योजना के पुनरीक्षित विधेयक में घाटा होने की स्थिति में कर के भुगतान को लेकर उद्योगों की चिंता का समाधान करने की कवायद की है। इस विधेयक को हाल ही में मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है।

संसद में पेश किए गए विधेयक के पहले के प्रारूप में कंपनियों के बीच यह डर फैल गया था कि अगर आयकर अधिकारियों द्वारा उनके घाटे को कम कर दिया जाता है तो उन्हें कर का भुगतान करना पड़ेगा।

अब पुनरीक्षित विधेयक में कंपनियों को विकल्प दिया गया है कि वे अपने घटे हुए नुकसान पर कर का भुगतान करने का विकल्प अपना सकती हैं और अपने पूरे घाटे को आगामी वर्षों की आमदनी में समायोजित कर सकती हैं। वैकल्पिक रूप से वे 25 प्रतिशत जुर्माने का भुगतान कर सकती हैं और कम किए गए घाटे को अपनी भविष्य की आमदनी में वे सिर्फ समायोजित कर सकती हैं।

उदाहरण के लिए अगर एक कंपनी ने 100 करोड़ रुपये घाटा दिखाया है। बहरहाल आयकर अधिकारी कंपनी की इस गणना से सहमत नहीं है और उसने घाटे को कम करके 50 करोड़ रुपये कर दिया। आमदनी छिपाने के लिए आयकर अधिकारी इसके लिए कंपनी पर 50 से 200 प्रतिशत तक जुर्माना लगाते हैं। वहीं कंपनी इसके खिलाफ आयुक्त (अपील) के पास जाती है और वहां मामला रखती है।

मूल विधेयक में प्रस्ताव किया गया था कि कंपनी इस योजना के तहत कर का भुगतान कर मामले का समाधान कर सकती है। कंपनियों ने यह मसला उठाया था कि वे घाटे पर कर का भुगतान क्यों करेंगी।

इस मसले के समाधान के लिए पुनरीक्षित योजना में अब कंपनी को दो विकल्प दिए गए हैं। कंपनी घटे हुए 50 करोड़ रुपये पर कर का भुगतान कर सकती है, जिसका खुलासा उसने नहीं किया है और पूरे 100 करोड़ रुपये घाटे को वह आगामी वर्षों में होने वाली आमदनी में समायोजित कर सकती है। कंपनियां इस तरह के नुकसान को 8 वर्षों तक आगे बढ़ा सकती हैं।

दूसरे विकल्प में कंपनी 25 प्रतिशत जुर्माने का भुगतान कर सकती है और सिर्फ 50 करोड़ रुपये नुकसान को आगे बढ़ा सकती है।

अशोक माहेश्वरी ऐंड एसोसिएट एलएलपी के पार्टनर अमित माहेश्वरी ने कहा, 'करदाताओं के मन में कर अधिकारी द्वारा दिखाए गए कम घाटे को लेकर दायर याचिका की स्थिति में योजना के लाभ को लेकर भ्रम का सामना नहीं करना पड़े।'

बीपीसीएल की ताजी निवेश प्रस्तुति के मुताबिक कंपनी यहां पर विपणन और अन्य बुनियादी सुविधाओं की योजना बना रही है। कंपनी अपने कुछ संयंत्रों को मुंबई से हटाकर इस नए स्थान पर स्थापित करने पर भी विचार कर रही है। नियोजित संयंत्रों को लगाने के लिए बीपीसीएल हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स (एचओसी) से जमीन खरीदने की प्रक्रिया में जुटी है।

उस व्यक्ति ने कहा, 'नियोजित निवेशों का दायरा 12,000 करोड़ रुपये से लेकर 13,000 करोड़ रुपये तक है जो वित्त वर्ष 2022 के पूंजीगत व्यय में जुड़ेगा जिससे उस साल का पूंजीगत व्यय 18,000 करोड़ रुपये के उच्च स्तर पर पहुंच जाएगा।'

हालांकि, उसने स्पष्ट किया कि वित्त वर्ष 2022 के सटीक पूंजीगत व्यय के बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि तब तक इसमें नए निवेशक शामिल हो चुके होंगे। अधिकारी ने कहा, 'हम परियोजना से मुंह नहीं मोड़ रहे बल्कि धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं। संयोग से जब कंपनी में नए निवेशक शामिल हो रहे होंगे तब बड़ी पूंजीगत व्यय की स्थिति बन रही होगी।' उसने स्पष्ट किया कि सरकार की तरफ से पूंजीगत व्यय को लेकर कोई रोक नहीं है।

20 नवंबर को सरकार ने तय किया था कि वह कंपनी में 53.29 फीसदी की अपनी समूची हिस्सेदारी बेचेगी और रणनीतिक खरीदार के हाथों में इसका प्रबंधन नियंत्रण सौंप देगी। इस मामले के जानकार लोगों ने कहा कि इसकी खरीदारी के लिए विदेशी बोलीदाताओं का ध्यान आकृष्ट हो सकता है क्योंकि ज्यादातर तेल उत्पादक कंपनियां भारत में अपने उत्पाद के लिए बाजार सुरक्षित करना चाहती हैं।

पुनरीक्षित विधेयक में यह योजना ज्यादा आकर्षक हो गई है क्योंकि न्यायाधिकरण मंचों और कर्ज वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) में लंबित याचिकाओं के समाधान की संभावना बढ़ी है। इस योजना में कम मूल्य के विवादों से संबंधित मामले भी शामिल होंगे।

संशोधित विधेयक में उन मामलों में भी फायदा मिलेगा, जिनमें करदाताओं के पक्ष में आदेश मिले हैं, लेकिन आयकर विभाग ने मामले को ऊपरी न्यायालय में चुनौती दी है।

कैबिनेट से मंजूरी मिली, अगले माह संसद में होगा पेश

- पुनरीक्षित विधेयक में कंपनियों को दो विकल्प दिए गए हैं
- कंपनी कम हुए घाटे पर कर भुगतान कर सकती है व पूरे घाटे को अगले 8 वर्षों तक समायोजित कर सकती है
- दूसरे विकल्प में कंपनी छुपाई राशि पर 25 प्रतिशत जुर्माने का भुगतान कर सकती है, शेष नुकसान को कंपनी आगे बढ़ा सकती है
- कंपनियों को डर था कि उन्हें घाटे पर करना होगा कर का भुगतान

अवैध सॉफ्टवेयरों का रेलवे टीम ने किया सफाया

रेलवे ने अवैध सॉफ्टवेयरों का सफाया करते हुए उन 60 एजेंटों को गिरफ्तार किया है जो ऐसे तरीकों से टिकटों की बुकिंग कर लेते थे। रेलवे के इस कदम से अब यात्रियों के लिए अधिक संख्या में तत्काल टिकट उपलब्ध हो सकेंगे। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के महानिदेशक अरुण कुमार ने कहा कि यात्रियों के लिए अब तत्काल टिकट घंटों तक उपलब्ध होंगे जो पहले बुकिंग खुलने के बाद कुछ मिनटों में ही समाप्त हो जाते थे।

अधिकारियों ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि एएनएमएस, मैक और जगुआर जैसे अवैध सॉफ्टवेयर आईआरसीटीसी के लॉगिन कैप्चा, बुकिंग कैप्चा और बैंक ओटीपी को बाईपास करते जबकि वास्तविक ग्राहकों को इन सभी प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। *भाषा*

नए निवेशक आने पर बीपीसीएल का अगला बड़ा पूंजीगत व्यय

अमृता पिल्लई
मुंबई, 18 फरवरी

ऐसे समय में जब केंद्र सरकार भारत पेट्रोलियम निगम (बीपीसीएल) से बाहर निकलने की दिशा में आगे बढ़ रही है, कंपनी के अगले भारी भरकम पूंजीगत व्यय के समय पर नए निवेशक इसमें शामिल हो रहे होंगे। हालांकि इसको लेकर अधिकारियों का कहना है कि यह महज संयोग है और पहले से ऐसी कोई योजना नहीं थी।

चालू वित्त वर्ष के लिए बीपीसीएल की नियोजित पूंजीगत व्यय 7,900 करोड़ रुपये के पार जा सकती है। अगले वित्त वर्ष में तेल विपणन कंपनी और 12,000 करोड़ रुपये खर्च करने पर विचार कर रही है। वित्त वर्ष 2022 में इससे भी अधिक खर्च करने की उम्मीद जताई जा रही है लेकिन तब बीपीसीएल के पास नए निवेशक होंगे। वित्त वर्ष 2022 की पूंजीगत व्यय योजनाओं के केंद्र में महाराष्ट्र के रसायनी में बीपीसीएल का नियोजित खर्च है। यहां पर फिलहाल भूमि अधिग्रहण का पेच फंसा हुआ है।

कंपनी की योजनाओं के बारे में सीधी जानकारी रखने रखने के एक व्यक्ति ने कहा, 'पूंजीगत व्यय का बड़ा हिस्सा रसायनी में खर्च किया जाएगा। हमने पहले रसायनी में जमीन के एक बड़े हिस्से का अधिग्रहण किया और अभी भी वहां पजेशन लेने की प्रक्रिया में जुटे हैं। जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम वहां और अधिक खर्च करने को इच्छुक नहीं हैं। हम रणनीति के तहत धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं ताकि स्थानीय और राजनेताओं के विरोध

आगे की राह

- बीपीसीएल वित्त वर्ष **2020** में करेगी करीब **8,000** करोड़ रुपये खर्च
- वित्त वर्ष **2021** में **12,000** करोड़ रुपये और खर्च करने की योजना
- वित्त वर्ष **2022** की पूंजीगत व्यय योजनाओं में **रसायनी** में निवेश को शामिल किया जाएगा
- नए निवेशक वित्त वर्ष **2022** की पूंजीगत व्यय योजनाओं को दे सकते हैं मजबूती
- **2022** की योजनाओं के लिए वैश्विक फंड जुटाने की पड़ सकती है जरूरत

पक्षियों को बचाने के लिए भूमिगत केबल पर हो विचार

उच्चतम न्यायालय ने विलुप्त हो रहे गोडावण पक्षी और इसी तरह के अन्य पक्षियों के उच्च क्षमता वाले बिजली के तारों से टकरा कर मारे जाने की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए राजस्थान सरकार से मंगलवार को कहा कि उसे बिजली के तार भूमिगत बिछाने पर विचार करना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि ये विशालकाय पक्षी हैं और इनके लिए उड़ान के मार्ग में पड़ने वाले उच्च क्षमता के बिजली के तारों से बचकर निकलना मुश्किल होता है। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत के पीठ की इस चिंता से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने भी सहमति व्यक्त की और कहा कि गोडावण पक्षी और खरमोर पक्षियों को बचाने के लिए भूमिगत केबल बिछाने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। *भाषा*

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 13 अंक 3

अच्छा प्रदर्शन

ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी) का क्रियान्वयन हाल के वर्षों के सबसे बड़े सुधारों में से एक रहा है। इसने कारोबारी माहौल सुधारने में भी मदद की है। ताजा आकलन के मुताबिक विश्व बैंक की कारोबारी सुगमता रैंकिंग के ऋणशोधन हल करने संबंधी मानकों पर भारत की स्थिति में 56 स्थानों का सुधार हुआ है। इसने देश की कुल रैंकिंग में भी 14 स्थानों का सुधार करने में मदद की और वह 190 देशों के बीच 63वें स्थान पर आ गया। विश्व बैंक के मुताबिक देश का ऋणशोधन निस्तारण ढांचा अब दक्षिण एशिया की कई अन्य अर्थव्यवस्थाओं से बेहतर है और यहां कम समय में रिकवरी बेहतर है।

बहरहाल, भारत को अभी भी अपने ऋणशोधन ढांचे को विकसित देशों के मानकों के अनुरूप बनाने के लिए लंबी दूरी तय करनी है। यह बात भारतीय ऋणशोधन एवं दिवालिया बोर्ड की ताजा तिमाही रिपोर्ट में भी नजर आई। आंकड़े बताते हैं कि दिसंबर तिमाही में चल रहे मामलों की तादाद पिछले साल की समान तिमाही की तुलना में दोगुनी हो गई। नकदीकरण के मामलों में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। दिसंबर 2016 में संहिता के अस्तित्व में आने के बाद से अब तक कुल 3,312 मामले दाखिल हुए हैं। करीब 190 मामलों में निस्तारण योजना स्वीकृत हुई जबकि 780 मामलों में नकदीकरण हुआ। हालांकि पहली नजर में नकदीकरण के मामलों की तादाद चौंकाने वाली लगती है लेकिन इसे संबंधित परिदृश्य में ही देखा जाना चाहिए। उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि इन कंपनियों में से 70 फीसदी या तो औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के साथ थीं या निष्क्रिय। दूसरी तरह से देखें तो ये वे मामले थे जहां ऋणशोधन ढांचे के अधीन आने के पहले ही मूल्य काफी हद तक समाप्त हो चुका था।

ऐसे में संभव है कि एक बार पुराने मामले हल होने के बाद नकदीकृत होने वाली कंपनियों की तादाद कम हो जाए। चाहे जो भी मौजूदा मामलों पर नीतिगत ध्यान देने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए प्रक्रिया के अधीन 1961 मामलों में से 30 फीसदी 270 दिन की अवधि पार कर चुके हैं। हालांकि सामान्य परिस्थितियों में यह प्रक्रिया 330 दिन में पूरी कर ली जानी चाहिए लेकिन जल्दी निस्तारण से व्यवस्था में मजबूती आएगी। ऐसे में दिवालिया निस्तारण व्यवस्था में क्षमता निर्माण करना जरूरी है। ऐसा करके ही मामलों को सहजता से हल किया जा सकता है। इसके लिए नियमित आकलन और राष्ट्रीय कंपनी लॉ पंचाट के पास पर्याप्त संसाधन आवंटित करने की आवश्यकता होगी।

निश्चित तौर पर सरकार ने आईबीसी को लेकर तीव्र गति से काम किया है। उदाहरण के लिए जब यह पता चला कि पिछले प्रबंधन की गड़बड़ियां सफल बोलीकर्ता के हित को प्रभावित कर सकती हैं तो उसने नए मालिकों के संरक्षण के लिए नियमों में संशोधन किया। इसी तरह उसने एक विपरीत निर्णय के बाद सुरक्षित ऋणदाताओं की प्रमुखता स्थापित करके कानून को मजबूती दी। ऋणशोधन निस्तारण प्रक्रिया की क्षमता में सुधार करने से देश की अर्थव्यवस्था को कई तरह से मदद करेंगे। यह ऋणदाताओं का जोखिम कम करने में मदद करेगा। इसके परिणामस्वरूप गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के शेयर कम करने और ऋण प्रवाह बढ़ाने में मदद मिलेगी। बड़े मामलों में रिकवरी नकदीकरण से अधिक रही है। उदाहरण के लिए एस्सार स्टील इंडिया के मामले में रिकवरी नकदीकरण मूल्य से 260 प्रतिशत ज्यादा थी। इसके अलावा सहज निस्तारण से अर्थव्यवस्था की ऋण संस्कृति में सुधार होगा। अब प्रवर्तकों के लिए निरंतर डिफॉल्ट के मामलों के बावजूद अपनी कंपनी पर काबिज रहना आसान नहीं होगा। व्यापक स्तर पर देखें तो इससे ऋण आवंटन किफायती होगा और वृद्धि को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

अजय मोहंती

आरसेप का विकल्प खुला रहे तो बेहतर

आरसेप व्यापार समझौते में न शामिल होकर भारत अपने लिए जोखिम पैदा कर रहा है। वह नियम बनाने वालों से नियम का पालन करने वालों की श्रेणी में शामिल हो सकता है। जानकारी दे रहे हैं **श्याम सरन**

भारत ने गत वर्ष क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसेप) में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया था। इस संधि से संबंधित वार्ता अंतिम दौर की ओर बढ़ रही है और वर्ष 2020 के अंत तक यह समझौता अंतिम रूप ले लेगा। भारत ऐसी क्षेत्रीय व्यापार व्यवस्था को स्वीकार करने को तैयार नहीं था जिसमें उसे आयात वृद्धि से निपटने की सीमित पात्रता थी। उत्पादों के मूल स्थान से संबंधित नियमों को लेकर कुछ मसले थे। मूल स्थान वाला मुद्दा पहले ही आपूर्ति शृंखला आधारित क्षेत्रीय रूप से एकीकृत व्यापार नेटवर्क में निहित है। आमतौर पर किसी भी कारोबारी साझेदार का उत्पाद कई अन्य देशों से आए घटकों और वस्तुओं से बनता है। किसी विशेष मुल्क को ध्यान में रखकर किए गए कारोबारी उपाय और शुल्क बहुत मायने नहीं रखते। भारत यदि इन आपूर्ति शृंखलाओं का हिस्सा नहीं है तो इसमें उसका ही नुकसान है। इसलिए क्योंकि विभिन्न कारोबारी साझेदारों के साथ अलहदा शुल्क व्यवहार एक जटिल कवायद है।

बहरहाल, यदि भारत मानता है कि उसके कारोबार का भविष्य क्षेत्रीय और वैश्विक आपूर्ति शृंखला का हिस्सा बनने में है तो आरसेप से बाहर रहने का निर्णय विरोधाभासी है। यदि भारतीय बाजार के आकार का लाभ लेते हुए आरसेप की आपूर्ति शृंखला में शामिल हुआ जाता कहीं अधिक बेहतर रणनीति होती। इससे बुनियादी ढांचे, व्यापार सुविधा उपायों और गुणवत्ता आदि में तत्काल सुधार देखने को मिलता क्योंकि आपूर्ति शृंखलाओं के लिए यह ज्यादा उपयोगी होता है। आपूर्ति शृंखला केवल कम शुल्क वाली व्यवस्था में कारगर हो सकती है जहां घटकों और कच्चे माल का उदारतापूर्वक आयात किया जा सके।

ताजातरीन आर्थिक समीक्षा में भी यह अनुशंसा की गई है कि भारत को चीन जैसा, श्रम आधारित निर्यात दायरा तैयार करना चाहिए और देश में बढ़ते युवाओं के लिए रोजगार के जबरदस्त अवसर तैयार करने चाहिए। यहां आवश्यकता यह है कि नेटवर्क उत्पादों पर ध्यान केंद्रित किया जाए। ये वे उत्पाद होते हैं जो तमाम मूल्य शृंखलाओं में तैयार होते हैं जहां असेंबली शृंखला बड़े पैमाने पर इनका उत्पादन करती हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से देश में असेंबलिंग का काम मेक इन इंडिया के साथ एकीकृत होगा। बजट पेश करते समय अपने भाषण में वित्त मंत्री ने आर्थिक समीक्षा की बात दोहराते हुए कहा कि भारत को नेटवर्क्ड वस्तुएं बनाने की आवश्यकता है। ऐसा करके वह वैश्विक मूल्य शृंखला का हिस्सा बन सकता है। इससे निवेश ज्यादा आता है और युवाओं को ज्यादा रोजगार प्राप्त होते हैं।

इस संदर्भ में भारत को भी आरसेप को लेकर खुले दिमाग का परिचय देना चाहिए। बाली में गत 3 और 4 फरवरी को आरसेप सदस्यों की अनौपचारिक बैठक में शामिल होने के आसियान के न्योते का सकारात्मक प्रत्युत्तर इसी क्रम में था। वार्ताकारों को असेंबल इन इंडिया नीति को बातचीत की टेबल पर लाना था। वह साझेदारों की हमारी कुछ चिंताओं को दूर करने की इच्छाशक्ति का भी परीक्षण कर सकता था। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह अवसर गंवा दिया गया। जैसा कि हमने पहले कहा आपूर्ति शृंखला कम शुल्क की व्यवस्था में काम करती है। जबकि बीते चार बजट में शुल्क बढ़ाया गया है। भारत आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण के 25 वर्ष के रुझान से पीछे हट रहा है। आयात प्रतिस्थापन की नीति तेजी से मजबूत हो रही है लेकिन उसका नीतिगत असर क्या होगा इसे लेकर भ्रम है। क्या नीतिगत चयन रुपये की कमजोर विनिमय दर में नहीं दिखना चाहिए? क्या विदेशी निवेश ऐसे क्षेत्रों में बुलाया जाना चाहिए जहां भारतीय कारोबारी कमजोर हैं?

वित्त मंत्री की बातों से भी स्पष्ट है कि देश संरक्षणवादी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, 'यह देखा गया है कि मुक्त व्यापार समझौतों के तहत होने वाला आयात बढ़ रहा है। इसके लाभ के अवांछित दावों से घरेलू उद्योग को खतरा पैदा हो गया है। ऐसे आयात पर कड़ी निगरानी की जरूरत है। इस संदर्भ में सीमा शुल्क अधिनियम में उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा रहे हैं। आने वाले महीनों में हम स्रोत आवश्यकता के नियम की समीक्षा करेंगे। खासकर चुनिंदा संवेदनशील वस्तुओं के बारे में ताकि यह सुनिश्चित हो कि मुक्त व्यापार समझौते नीतिगत दिशा के साथ सामंजस्य में हों।'

सीमा शुल्क में ऐसा ही एक प्रस्तावित संशोधन उल्लेखनीय है। अधिनियम की धारा 11 (2) का एक प्रावधान केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि वह देश की अर्थव्यवस्था को सोने या चांदी के अनियंत्रित आयात या निर्यात से होने वाले नुकसान से बचाए। इस प्रावधान में संशोधन कर इसमें सोने और चांदी के अलावा 'कोई अन्य वस्तु' का प्रावधान जोड़ना चाहती है। यह एक अहम व्यापार प्रतिबंध वाला उपाय होगा और यह स्पष्ट नहीं है कि यह विश्व व्यापार संगठन के साथ हमारे नए दायित्वों के अनुरूप होगा या नहीं।

अब ज्यादातर वैश्विक व्यापार व्यापक क्षेत्रीय समझौतों के अधीन होते हैं। उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता, यूरोपीय संघ और लैटिन अमेरिका की में ऐसी व्यवस्थाएं हैं। आरसेप एशिया में उनका समकक्ष होगा। विश्व व्यापार संगठन की भूमिका कमजोर पड़ी है और अबाध व्यापार और निवेश प्रवाह की अवधारणा के साथ, खासकर विकासशील देशों में, हम तेजी से विश्व व्यापार व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। यह प्रत्युत्तर के सिद्धांत पर आधारित होगा और व्यापार प्रवाह पर शुल्क का असर कम तथा मानकों, विशिष्टताओं, बौद्धिक संपदा संबंधी उपायों तथा पर्यावरण मानक का असर अधिक होगा। इस नई विश्व व्यवस्था की निगरानी सुधरे हुए और पुनर्गठित विश्व व्यापार संगठन के हाथ होगी। चीन और अमेरिका जैसे बड़े कारोबारी देशों के अलावा अन्य देशों के लिए यहां सीमित गुंजाइश होगी तथा बड़े क्षेत्रीय कारोबारी समझौते अहम होंगे। भारत का विदेश व्यापार वैश्विक व्यापार के दो फीसदी से कम है। यदि भारत इन समझौतों में से किसी का हिस्सा नहीं बना तो वह नियम बनाने वालों में नहीं रह जाएगा। इस पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए क्योंकि हमारी भविष्य की आर्थिक संभावनाएं इससे जुड़ी हैं।

सन 1991 में जब भारत ने आर्थिक सुधार और उदारीकरण की नीतियां अपनाईं तब आशंका थी कि देश का उद्योग जगत लड़खड़ा जाएगा। ये आशंकाएं निर्मूल साबित हुईं और भारत स्थायी रूप से उच्च वृद्धि पथ पर वापस आ गया। सफल आर्थिक नीति को छोड़ने और नाकाम आयात प्रतिस्थापन को को अपनाने का क्या तुक है? देश को वैश्विक असेंबली हब बनाने और उसके बाद विपरीत नीतियां अपनाने की बात अनुपयुक्त है।

(लेखक पूर्व विदेश सचिव और सीपीआर के सीनियर फेलो हैं)

फंडों के बेहतर संचालन के लिए सेबी का अहम कदम

बाअदब

सोमशेखर सुंदरेशन

सेबी द्वारा बनाए गए स्टीवर्डशिप कोड का एक सिद्धांत यह भी है कि संस्थागत निवेशकों को निवेश कंपनियों पर नजर रखनी चाहिए। सूचीबद्ध कंपनियों और उनके अंदरूनी सूत्रों को भेदिया कारोबार पर पाबंदी से जुड़े नियमों को मानना होगा।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने म्युचुअल फंड उद्योग और वैकल्पिक निवेश फंडों के लिए स्टीवर्डशिप कोड बनाकर फंडों के कामकाज में सुधार की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। यह संहिता कोई नियमों का पुलिंदा नहीं है बल्कि सिद्धांतों पर आधारित एक कानून है जो 1 अप्रैल से लागू होगा।

यह ढांचा इस बात की पहली वैधानिक स्वीकारोक्ति है कि संस्थागत निवेशकों और कंपनी संचालन में शामिल लोगों के बीच बातचीत की गुंजाइश मौजूद है। यह ऐसी गुंजाइश है जो भेदिया कारोबार के आरोपों की आशंका के कारण सिकुड़ती जा रही है। यह सही नजरिया है और इस परंपरागत दिखावे से अलग है कि इस तरह की बातचीत के लिए कोई जगह नहीं है। स्टीवर्डशिप कोड के तहत इस गुंजाइश को स्वीकार किया गया है और यह संस्थागत निवेशकों को कंपनी बोर्ड के साथ बातचीत में सक्षम बनाएगा। साथ ही इसके लिए कंपनियों को बाहरी दुनिया के साथ अपने संवाद की अपनी शर्तों को कमजोर करने की जरूरत नहीं है।

सेबी द्वारा बनाए गए स्टीवर्डशिप कोड का एक सिद्धांत यह भी है कि संस्थागत निवेशकों को निवेश कंपनियों पर नजर रखनी चाहिए। सूचीबद्ध कंपनियों और उनके अंदरूनी सूत्रों को भेदिया कारोबार पर पाबंदी से जुड़े नियमों को मानना होगा। उन्हें संवाद और शेयरधारकों के लिए खुलासे की जानकारी के लिए नीतियां बनानी होंगी ताकि दुनिया को उनके बारे में जानकारी मिल सके। संस्थागत निवेशकों और कंपनी प्रशासन के नजरिये के बीच टकराव से तनाव बढ़ेगा जिससे कंपनियों के निदेशक अपने कामकाज के प्रति सचेत होंगे।

एक अन्य सिद्धांत के तहत संस्थागत निवेशकों के पास अपने हस्तक्षेप के बारे में एक नीति होनी चाहिए, वोटिंग नीति होनी चाहिए और उन्हें दूसरे संस्थागत निवेशकों के साथ सहयोग करना चाहिए। संस्थागत निवेशकों की वोटिंग नीति से संस्थागत निवेशकों के नजरिये के बारे में पारदर्शिता आएगी। म्युचुअल फंड के लिए बिल्कुल सही हो सकती है। उदाहरण के लिए यह नीति ऐसी हो सकती है कि अगर वे एक निवेश कंपनी के प्रस्ताव से खुश नहीं हैं तो उन्हें इसके पक्ष में या खिलाफ वोटिंग में समय बरबाद करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन वे निवेश की बिक्री पर विचार कर सकते हैं। इससे निवेश कंपनियों के कामकाज में शामिल लोगों को यह संदेश जाएगा कि उन्हें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है जहां निवेशक अपने शेयर बेच सकता है या इसके खिलाफ वोटिंग कर सकता है। यानी निवेशक की हिस्सेदारी का आकार और इसके प्रति उसके आक्रामक रुख से कंपनी को यह संकेत मिल जाएगा कि निवेशक के हस्तक्षेप के जोखिम को किस तरह संभाला जाए।

सही काम करने के लिए नियामकीय दिशानिर्देश अच्छा तरीका नहीं है लेकिन सुशासन हासिल करने के लिए भारत में नियम आधारित कानून की कमी को देखते हुए सिद्धांतों पर आधारित स्टीवर्डशिप कोड को एक मौका दिया जाना चाहिए। कंपनी कामकाज से जुड़े अधिकांश मुद्दों को हल्के में लिया जाता है।

कंपनी के मालिकाना हक का भाव प्रवर्तकों और शेयरधारकों के बीच इतना गहरा है कि यह न्यायिक नजरिये में भी दिखता है। एक मजबूत व्यवस्था के अभाव में न्यायिक प्रक्रिया भी एक तरह से ठहर गई है। न्यायपालिका के पास संसाधनों की भारी कमी है और हर पार्टी की सरकार ने न्यायपालिका को कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। न्यायपालिका के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा, मानव संसाधन और व्यवस्थाएं मुहैया नहीं कराई गई। सरकारें चाहती हैं कि उसके कामकाज में न्यायपालिका का हस्तक्षेप कम से कम हो। इस स्थिति से कंपनी जगत का कार्यकारी हिस्सा भी प्रभावित हुआ है। आज भी अगर कोई किसी कंपनी में संस्थागत हस्तक्षेप की बात करता है तो वकील एलआईसी बनाम एस्कॉर्ट्स वाद में उच्चतम न्यायालय के फैसले का जिक्र करने लगते हैं। यह फैसला 1980 के दशक में दिया गया था जो पूरी तरह अलग दौर था जब सूचीबद्ध कंपनियों में शेयरधारकों के हितों को लेकर इतना झमेला नहीं था।

यह सही है कि स्टीवर्डशिप कोड सभी समस्याओं के लिए रामबाण नहीं है। आप देख सकते हैं कि कैसे इसे संस्थागत निवेशकों के खिलाफ लागू किया जाता है। जो सिद्धांतों का उल्लंघन करेगा, वह समस्याओं का सामना करेगा। सेबी अगर इस कोड को अपने हिसाब से चलने दे तो बेहतर होगा। इसे परंपरागत कानूनों की तरह लागू नहीं किया जाना चाहिए। ज्यादा चौकस रहने से इसके लक्ष्यों को पाने की बेहतर संभावना होगी।

(लेखक वकील और स्वतंत्र सलाहकार हैं।)

कानाफूसी

उत्साहित अखिलेश

दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की शानदार जीत से उत्साहित समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने न केवल उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर हमले तेज कर दिए हैं बल्कि उन्होंने 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों में अपनी पार्टी की चुनावी संभावनाओं पर भी बात करना आरंभ कर दिया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम के आलोचक रहे यादव लोगों से कह रहे हैं कि वे किसी भी तरह का फॉर्म न भरें। वर्ष 2022 के चुनाव में भाजपा को पराजित करने की आशा के साथ सपा प्रमुख ने हर किसी को आश्वस्त किया है कि उनकी अगली सरकार जाति जनगणना कराएगी। उन्होंने यह भी कहा है कि सत्ता में आने के बाद समाजवादी पेंशन को दोबारा शुरू किया जाएगा। भाजपा सरकार आने के बाद इस पेंशन को बंद कर दिया गया था।

आलोचना का नया स्वर

राजधानी नई दिल्ली में एक नई त्रिकोणीय संसद समेत सेंट्रल विस्टा को नए सिरे से विकसित करने की योजना है। एक ऐसे व्यक्ति ने इस योजना की आलोचना की है जिससे इसकी अपेक्षा नहीं थी। सोमवार को महात्मा गांधी पर एक पुस्तक के लोकार्पण समारोह में जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने महात्मा की प्रासंगिकता पर भाषण दिया, वहीं उसी आयोजन में लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप ने उक्त योजना पर सवाल उठा दिए। कुछ अनुमानों के मुताबिक नई योजना पर करीब 20,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाने हैं। कश्यप ने कहा कि नई इमारतों के निर्माण से अमीरों और गरीबों के बीच की खाई और चौड़ी होगी। उन्होंने कहा कि नई इमारतों की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि मौजूदा संसद भवन की स्थिति अभी अच्छी है। इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कहा कि देश के राजनेताओं का दिखावा मुगलों से कम नहीं है। इस पुनर्विकास योजना को लेकर सरकार के भीतर भी असहमति के स्वर सुनाई दे रहे हैं लेकिन अभी तक किसी ने इस पर खुलकर सवाल उठाने का साहस नहीं दिखाया है।

आपका पक्ष

बेटियों को भी आगे बढ़ने का मौका मिले

उच्चतम न्यायालय ने सेना में महिला अधिकारियों के स्थायी कमीशन पर फैसला देते हुए सरकार को दिशानिर्देश दिए कि सेना में महिला अधिकारियों को पुरुष अधिकारियों की तरह नौकरी के नियम बनाए जाएं। उच्चतम न्यायालय ने यह भी माना कि कमांड पोस्ट के लिए भी महिलाएं योग्य हैं। अदालत के इस फैसले के बाद सेना से जुड़ी और सेना में जाने की तैयारी कर रही महिलाएं व लड़कियां खुश हैं। आज हमारे देश की लड़कियां हर क्षेत्र में लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। सरकार भी लड़कियों को करियर बनाने और अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए इनके लिए विशेष योजनाएं चला रही हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज जब देश की लड़कियां हर क्षेत्र में अपना दबदबा कायम कर रही हैं, फिर भी देश में ऐसे संकीर्ण सोच वाले लोगों की कमी नहीं है जो अब भी लड़कियों को कमजोर समझते हैं। उन्हें लड़कों

उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का निर्देश दिया

के बराबर आगे बढ़ने का मौका नहीं देते हैं। खासतौर पर गांवों में ऐसी स्थिति देखने को मिलती है जबकि हमारा देश गांवों में ही बसता है। सरकार द्वारा लड़कियों की कामयाबी, इनके करियर के लिए जो भी योजनाएं अमल में लाई जाती हैं और भारत सशक्त तब तक नहीं हो सकता, जब तक हर वर्ग के सत-प्रतिशत लोग लड़का-लड़की के बीच भेदभाव की संकर्णि मानसिकता नहीं त्यागते और सरकार के बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ पर अमल नहीं करते।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

सहकारी बैंकों के नए नियमन

बैंकों के दिवालिया होने पर ग्राहकों की जमा राशि एक लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने का केंद्र सरकार का कदम सराहनीय है। सरकार ने देश के सभी सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक नियमन के तहत लाने की भी बात कही है जो पंजाब ऐंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक जैसे संकटों से निपटने में मददगार होगा। हालांकि प्रशासनिक व्यवस्था अभी भी यथावत राज्य सरकार के दायित्व वाली संस्था के पास रहेगी। लेकिन रिजर्व बैंक के नियमन से कहीं न कहीं सहकारी बैंकों की मूल भावना प्रभावित हो सकती है। सहकारी बैंकों की पहचान दूर-सुदूर तक है जिससे आम लोगों के काम आसानी से हो जाते हैं। बहरहाल पारदर्शी तंत्र का निर्माण बैंकिंग व्यवस्था की मूल अवधारणा है, बशर्ते सहकारी बैंकों के असली लाभार्थियों को इससे तकलीफ नहीं हो।

भूपेंद्र सिंह रंगा, पानीपत

मतदान प्रतिशत कम होना चिंतनीय

वर्तमान में होने वाले चुनावों में मतदान प्रतिशत संतोषजनक दिखाई नहीं पड़ रहा है। डिजिटल युग में भी मतदान प्रतिशत पिछड़ रहा है। आज सबके पास मोबाइल है तथा आधार कार्ड जैसा प्रामाणिक दस्तावेज है। मतदाता पहचान पत्र पाना अब कोई दूर की कौड़ी नहीं है। ऑनलाइन सेवा से यह सभी कार्य आसान हो गए हैं। राजनीतिक दल पहचान पत्र जुटाने और मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने में नागरिकों की मदद करते हैं। इसके बाद भी अचरज होता है कि मतदान 60 प्रतिशत के आसपास ही रहता है। चुनाव आयोग अगर मतदान का न्यूनतम प्रतिशत अनिवार्य कर दे तो संभव है मतदान प्रतिशत में इजाफा हो।

हिम्मत जोशी, नागपुर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

गोल्ड ईटीएफ का एयूएम 30 फीसदी बढ़ा

समी मोडक और दिलीप कुमार झा
मुंबई, 18 फरवरी

सोने की कीमतों में भारी बढ़त से घरेलू निवेशकों का गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंडों (ईटीएफ) की तरफ फिर से रुझान बढ़ा है। म्युचुअल फंडों के गोल्ड ईटीएफ में जनवरी में 202 करोड़ रुपये की शुद्ध आवक हुई है, जो दिसंबर 2012 से सबसे अधिक है। पिछले 12 महीनों के दौरान गोल्ड ईटीएफ में औसत आवक महज 16 करोड़ रुपये रही है। इसके अलावा गोल्ड ईटीएफ की प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियां (एयूएम) बढ़कर 6,207 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है, जो सितंबर 2016 से सबसे अधिक है। पिछले एक महीने के दौरान परिसंपत्तियों में 30 फीसदी से अधिक बढ़ोतरी हुई है। सोने की कीमतों में 20 फीसदी बढ़ोतरी से परिसंपत्तियों में वृद्धि हुई है। विशेषज्ञों ने कहा कि निवेशकों को बीते वर्षों का प्रतिफल लुभा रहा है, इसलिए वे गोल्ड ईटीएफ में निवेश कर रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल फाइनैंशियल सर्विसेज के सहायक निदेशक किशोर नार्ने ने कहा, 'निवेशक हमेशा सोना या अन्य परिसंपत्ति खरीदते समय पिछले प्रतिफल को देखते हैं। सोने ने पिछले एक साल में 22 फीसदी और पिछले दो वर्षों में 33 फीसदी प्रतिफल दिया है।' सोने की कीमतों में और बढ़ोतरी की उम्मीद है, जिससे गोल्ड ईटीएफ में निवेश की आवक आगे भी बनी रह सकती है। नार्ने ने कहा, 'वैश्विक अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है, इसलिए उसे मौद्रिक नरमी की जरूरत है। ऐसे में सोने की कीमतें अगले छह महीनों में कम से कम 10 फीसदी बढ़ने के आसार हैं। वहीं ब्याज दरों में गिरावट आ रही है, इसलिए निवेशक जोखिम वाली परिसंपत्तियों के बजाय सुरक्षित परिसंपत्तियां तलाश रहे हैं।'

अनाज भंडारण की होगी समस्या

इस बार होगा गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन, कम पड़ सकते हैं एफसीआई के गोदाम

संजीव मुखर्जी
नई दिल्ली, 18 फरवरी

इस बार गेहूं के रिकॉर्ड उत्पादन से भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के लिए भंडारण की समस्या पैदा हो सकती है। आज जारी दूसरे अग्रिम अनुमानों के मुताबिक आने वाली गेहूं की फसल का उत्पादन अब तक का सबसे अधिक 1,062 लाख टन रहेगा। ऐसे में अगर एफसीआई ने आगामी महीनों में पहले के अनाज भंडार को जल्द बेचने के लिए कदम नहीं उठाए तो उसे भंडारण की समस्या से जूझना पड़ सकता है।

सरकार के लिए 2020-21 में नए गेहूं की आवक के लिए भंडारण स्थान की व्यवस्था करना एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। आज जारी आंकड़ों में दिखाया गया है कि जुलाई 2019 से शुरू फसल वर्ष 2019-20 में गेहूं का अनुमानित उत्पादन 2018-19 से 26.1 लाख टन और इस वर्ष के लक्ष्य से 57.1 लाख टन अधिक है।

अगर बीते वर्षों की तरह यह मानकर चलते हैं कि एफसीआई और राज्य एजेंसियां गेहूं के इस भारी उत्पादन में से करीब 30 से 35 फीसदी खरीदारी करती हैं तो पहले से मौजूद स्टॉक में 280 से 370 लाख टन का इजाफा होगा। इससे एफसीआई की पहले से ही कमजोर वित्तीय स्थिति पर और दबाव बढ़ेगा। वित्त वर्ष 2021 के बजट दस्तावेज के मुताबिक एफसीआई 2020-21 में राष्ट्रीय लघु बचत कोष (एनएसएसएफ) से 24 फीसदी अधिक यानी 1.36 लाख करोड़ रुपये का कर्ज लेगा।

आंकड़े दर्शाते हैं कि केंद्रीय भंडार में खाद्यान्न (गेहूं एवं चावल) का कुल स्टॉक 7 फरवरी 2020 को करीब 578.1 लाख टन अनुमानित था। इसमें गेहूं का स्टॉक 303.6 लाख टन अनुमानित था, जो जरूरत से 124 फीसदी अधिक है। वहीं चावल का स्टॉक 274.1 लाख टन अनुमानित है, जो हर साल 1 जनवरी को जरूरी स्टॉक से 260 फीसदी अधिक है।

एक जनवरी को एफसीआई और राज्य एजेंसियों के पास 758.1 लाख टन का भंडारण स्थान था। वित्त वर्ष 2019-20 में केंद्र के लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए 603.9 लाख टन का आवंटन करने का अनुमान है, जो खरीद के मुकाबले काफी कम है।

इस बीच दूसरे अग्रिम अनुमानों में दर्शाया गया है कि रबी की अन्य प्रमुख फसलों में चने का उत्पादन 112.2 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले साल से 12.80 फीसदी अधिक है। रबी सीजन में उगाई जाने वाली सबसे बड़ी तिलहन फसल सरसों का उत्पादन मामूली गिरकर 91.1 लाख टन रहने का अनुमान है, जो पिछले साल से 1.54 फीसदी कम है।

दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक रबी सीजन के सभी खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 1,496 लाख टन रहने का अनुमान है, जो पिछले साल से 4.10 फीसदी अधिक है। देश में रबी और खरीफ दोनों फसलों का उत्पादन 2019-20 में 2,919.5 लाख टन रहने का अनुमान है, जो 2018-19 के मुकाबले 2.36 फीसदी अधिक है।

सरकार ने दूसरे अग्रिम अनुमानों में खरीफ सीजन 2019-20 में दलहन के उत्पादन का अनुमान भी पहले अग्रिम अनुमान के मुकाबले घटाया है। पहला अग्रिम अनुमान पिछले साल सितंबर में जारी किया गया था। दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ सीजन 2019-20 में दलहन का उत्पादन 79.2 लाख टन अनुमानित है, जो पहले अग्रिम अनुमान 82.3 लाख टन से कम है। इसकी वजह यह है कि अब उड़द उत्पादन का अनुमान 17.2 लाख टन कर दिया गया है, जो पहले 24.3 लाख टन का अनुमान था।

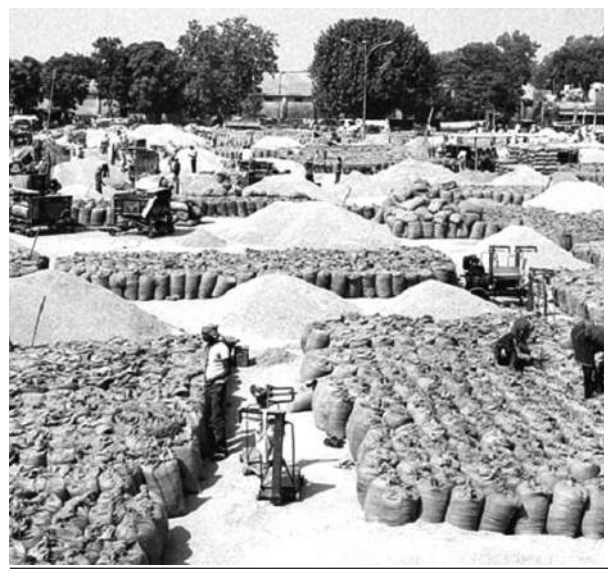

भंडारण संकट

- अग्रिम अनुमानों के मुताबिक आने वाली गेहूं की फसल का उत्पादन अब तक का सबसे अधिक 1,062 लाख टन हो सकता है
- एफसीआई अनाज भंडार को जल्द बेचने के लिए कदम नहीं उठाए तो भंडारण स्थान की समस्या हो सकती है
- एफसीआई और राज्य एजेंसियां गेहूं उत्पादन में से करीब 30 से 35 फीसदी खरीदारी करती हैं तो पहले से मौजूद स्टॉक में 280 से 370 लाख टन का इजाफा होगा

1,062.1 लाख टन
2019-20 में गेहूं उत्पादन का अनुमान
(दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक)

303.6 लाख टन
1 फरवरी 2010 को गेहूं का भंडार (जरूरत से 124 फीसदी अधिक)

603.9 लाख टन
2019-20 में पीडीएस और अन्य योजनाओं के लिए आवंटन (इसमें 253.8 लाख टन गेहूं और 349 लाख टन चावल है)

758.4 लाख टन
दिसंबर 2019 में भंडारण स्थान की स्थिति (इसमें 626.4 लाख टन कवर्ड और शेष सीएपी है)

स्रोत : सरकारी एजेंसियां

चीनी निर्यात पकड़ रहा जोर

राजेश भयानी
मुंबई, 18 फरवरी

इस सत्र के दौरान अप्रत्याशित रूप से चीनी निर्यात में इजाफा हो रहा है तथा और निर्यात के मौके भी सामने आ रहे हैं। उम्मीद है कि इंडोनेशिया भी जल्द ही भारत की चीनी के लिए अपना द्वार खोल देगा। पिछले कुछेक सालों से उद्योग को चीनी की जिस अधिकता से जूझना पड़ रहा है, उससे छुटकारा पाने के लिए उत्पादन में कमी के साथ-साथ निर्यात में इजाफा होना फायदेमंद है।

सरकार ने निर्यात कोटे का पुन: आवंटन करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जो मिलें इस कोटे का इस्तेमाल नहीं कर पाई हैं, वह उन मिलों को दिया जाएगा जिन्होंने अधिक कोटे की मांग की है। सरकार ने बड़े उपाय के तौर पर आज जारी एक परिपत्र में उन मिलों को चेताया भी है जो निर्यात कोटे का इस्तेमाल नहीं कर पा रही हैं और उसे छोड़ भी नहीं रही हैं। ऐसी मिलों ने चीनी का जो बफर स्टॉक रखा हुआ है, उसके लिए वे तीसरी या चौथी तिमाहियों के लिए अपने दावों की हकदार नहीं होंगी। इससे यह सुनिश्चत होगा कि चीनी निर्यात का और अधिक कोटा पूरा किया जा रहा है।

इस्मा के अनुसार कुछ चीनी मिलों ने न्यूनतम स्वीकार्य निर्यात मात्रा (एमएईक्यू) यानी निर्यात कोटा सरकार को दे दिया है या दे देंगी। यह वह कोटा है जिसे वे पूरा करने की स्थिति में नहीं हैं। भारतीय चीनी मिल संघ (इस्मा) और व्यापार प्रमुखों का अनुमान है कि इस सत्र में 50 लाख टन निर्यात होगा। सरकार ने मिलों के हिसाब से एमएईक्यू जारी किया है। सरकार ने 60 लाख टन चीनी निर्यात का कोटा जारी किया था।

निर्यातकों का कहना है कि करीब 16 से 17 लाख टन चीनी का निर्यात किया जा चुका है और निर्यात के लिए तकरीबन 32 से 33 लाख टन अनुबंध किए जा चुके हैं।

- इस सत्र में 50 लाख टन निर्यात होने का इस्मा और व्यापार प्रमुखों का अनुमान
- सरकार ने 60 लाख टन निर्यात कोटा जारी किया था

अक्टूबर में जब सत्र शुरू हुआ तो कच्ची चीनी के लिए प्रति टन 21,000 रुपये मिल रहे थे, जबकि घरेलू बाजार में न्यूनतम बिक्री मूल्य प्रति टन 31,000 रुपये था, लेकिन अब निर्यातकों को प्रति टन 24,000 रुपये मिल रहे हैं। सरकार द्वारा घोषित सब्सिडी 10,480 रुपये प्रति टन है। इसका अर्थ यह है कि महाराष्ट्र में मिलों को स्थानीय बिक्री में प्रति किलोग्राम 31 से 32 रुपये मिल रहे हैं, जबकि सब्सिडी के साथ उन्हें निर्यात में औसतन 34 रुपये प्रति किलोग्राम मिल रहे हैं।

इस बारे में जानकारी रखने वाले सूत्रों ने यह भी कहा कि अंतत: इंडोनेशिया ने भारत से चीनी आयात शुरू करने का फैसला कर लिया है। पिछले करीब दो सालों से दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही थी। उम्मीद है कि इंडोनेशिया आईसीयूएमएसए स्तर का इस्तेमाल करेगा ताकि भारत का चीनी उद्योग कच्ची चीनी का निर्यात कर सके। उसने न्यूनतम 1,200 आईसीयूएमएसए तय किया है, लेकिन भारत की मिलें इतने अधिक स्तर की कच्ची चीनी का उत्पादन नहीं करती हैं। अब सूत्रों का मानना है कि भारतीय मिलों के लिए यह स्तर कम करके 500 से 600 कर दिया जाएगा। इस संबंध में औपचारिक घोषणा किए जाने की उम्मीद है।

इस्मा ने मौजूदा उत्पादन के संबंध में आज जारी एक नोट में यह भी कहा है कि वैश्विक बाजार में चीनी सत्र 2019-20 के दौरान 80 से 90 लाख टन की कमी आने का अनुमान है और थाईलैंड में कम उत्पादन की वजह से उसके निर्यात में 30 से 40 लाख टन कमी आने के आसार हैं। आने वाले महीनों में भारतीय चीनी निर्यात में तेजी आ सकती है और पूरे सत्र में 60 लाख एमएईक्यू के मुकाबले 50 लाख टन से अधिक एमएईक्यू प्राप्त किया जा सकता है।

हालांकि अखिल भारतीय चीनी व्यापार संघ के अध्यक्ष प्रफुल्ल विठलानी ने चिंता जताई है कि सब्सिडी समय पर नहीं आती है। इससे कार्यशील पूंजी लागत बढ़ जाती है। कुछ मिलों को अब तक पिछले साल की सब्सिडी नहीं मिली है। इसके अलावा गन्ने की कम उपलब्धता के कारण महाराष्ट्र में चीनी मिलों द्वारा एक महीने में परिचालन बंद किए जाने की संभावना है और उत्तर प्रदेश में मिलें मध्य अप्रैल तक परिचालन बंद कर सकती हैं। विठलानी ने कहा कि इसके बाद मिलें कच्ची चीनी का और उत्पादन नहीं करेंगी। इसलिए निर्यात की अवधि छोटी है। अत: उद्योग के सभी प्रतिनिधियों को जोखिम लेकर बाद में निर्यात करने के लिए और अधिक कच्ची चीनी उत्पादन का फैसला करना चाहिए।

15 फरवरी, 2020 तक मिलों ने 1.698 करोड़ टन चीनी उत्पादन किया है, जबकि पिछले वर्ष की इसी तारीख को 2.196 करोड़ टन उत्पादन किया गया था। गन्ना उपलब्ध नहीं होने की वजह से 23 चीनी मिलों ने पहले ही पेराई कार्य बंद कर दिया है। महाराष्ट्र में अब तक उत्पादन गिरकर 43.4 लाख टन रह गया है, जबकि पिछले साल उत्पादन 83 लाख टन था। विभिन्न अनुमान बताते हैं कि इस साल राज्य में 60 से 70 लाख टन उत्पादन होगा। उत्तर प्रदेश में 66.3 लाख टन चीनी उत्पादन किया गया है, जो पिछले साल की तुलना में करीब पांच प्रतिशत ज्यादा है।

चीन से आयात पर शुल्क घटाने की मांग

चीन से भारत का आयात वर्ष 2018-19 में 70 अरब डॉलर तक रहा। चीन व्यापारिक वस्तुओं का सबसे बड़ा स्रोत है

शुभायन चक्रवर्ती

चीन में कोरोनावायरस संक्रमण में कमी के कोई बड़े संकेत न मिलने से घरेलू उद्योगों ने सरकार के सामने विशेष कदम उठाने की गुहार लगाई है ताकि भविष्य में कमी के असर से बचा जा सके। वायरस से प्रभावित चीन में रोजाना संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं और फैक्टरियां अब भी बंद हो रहे हैं। चीन से भारत का आयात वर्ष 2018-19 में 70 अरब डॉलर का रहा और पड़ोसी देश मर्केंडाइज (व्यापारिक वस्तुओं) का सबसे बड़ा स्रोत रहा। भारत के 20 प्रमुख आयात में चीन 43 फीसदी की आपूर्ति करता है। हालांकि सरकार वैकल्पिक बाजारों से आयात करने के लिए पूरी सक्रियता दिखा रही है और चीन से आयात महंगा करने की कोशिश में है।

अब भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने वित्त मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से कहा है कि इस संकट से जूझने के लिए त्वरित कदम उठाएं जाएं। सीआईआई ने यह भी कहा है कि पहले चीनी वस्तुओं पर जो आयात शुल्क बढ़ाया गया था उसे वापस लिया जाए क्योंकि इन वस्तुओं की कीमतों के बढ़ने के आसार हैं। सीआईआई के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया, 'चीन की फैक्टरियां जितने लंबे समय तक बंद रहेंगी, वैश्विक स्तर पर उतनी ही हलचल दिखेगी क्योंकि प्रत्येक देश वैकल्पिक स्रोत से अहम वस्तुओं के निर्यात पर ध्यान देगा। इस बीच भारतीय उपभोक्ताओं के लिए ज्यादा आयात शुल्क के साथ वस्तुओं का आयात करना काफी महंगा साबित होगा।'

उद्योग चाहता है कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को एनपीए (फंसे कर्ज) नियमन से एक बार तीन महीने तक की लंबी आपातकालीन छूट मिले ताकि कर्ज के डिफॉल्ट होने के जोखिम को कम किया जा सके क्योंकि इस वक्त आपूर्ति शृंखला में दिक्कत दिख रही है। इससे चीन के निर्यातकों को फायदा भी मिल सकता है जो राजस्व घाटे से जूझ रहे हैं।

विनिर्माण इकाइयों को शीघ्र कर्ज आवंटन समेत क्रेडिट सुविधा देने का भी सुझाव दिया गया है। उद्योग संगठनों के अनुसार, जिन देशों में अंतिम उत्पाद तथा

- चीन में कोरोनावायरस संक्रमण से मरने वालों की तादाद में दिखने लगी कमी
- 30 जनवरी के बाद से नए संक्रमण की तादाद पहली बार 2,000 से कम हो गई
- विशेषज्ञों का कहना है कि चीन में वायरस पर नियंत्रण हो जाने की बात करना जल्दबाजी है

भारत के 20 प्रमुख आयात में चीन की 43 फीसदी है हिस्सेदारी (फाइल फोटो)

कच्चे माल की कीमतें ज्यादा है, ऐसे देशों से आयात करने पर भारत में सामान की कीमतें बढ़ जाएंगी। इसी तरह, चीन से आयात में आई कमी को भरने के लिए अगर घरेलू विनिर्माण इकाइयां स्थापित की गईं तो इसके लिए भी पूंजी की आवश्यकता होगी।

अधिकारियों का कहना है कि घरेलू उद्योग ने सरकार से प्रोत्साहन तथा दूसरे तरीकों के माध्यम से जल मार्ग द्वारा सामान लाने वाली कंपनियों को चीन से आयात के लिए बाध्य करके के लिए कहा है। फिलहाल कंपनियां चीन से सामान लाने से मना कर रही हैं।

खबरों के अनुसार फार्मास्युटिकल क्षेत्र का आयात इस महीने के अंत तक बाधित हो जाएगा और इस क्षेत्र की कंपनियों ने सरकार से कच्चे माल, एपीआई, जरूरी रसायनों की खरीद तथा विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय द्वारा मंजूरी प्रक्रिया को तेज करने की मांग की गई है। भले ही भारतीय कंपनियों के पास तकनीकी क्षमताएं हैं, लेकिन वे उत्पादों की गुणवत्ता या फॉर्मूले में सुधार पर अधिक ध्यान देते हैं और चीन के मुकाबले लागत अधिक हो जाती है।

सौर ऊर्जा संबंधी क्षेत्र के लिए सीसीआई ने कहा कि 2-4 गीगावॉट वाली आगामी परियोजनाएं प्रभावित हो सकती हैं क्योंकि इससे जुड़े 90 प्रतिशत आयात चीन से आते हैं। पिछले साल आयातित सौर पैनल पर आयात शुल्क बढ़ाने से इस साल भारत की सौर ऊर्जा परियोजना प्रभावित हुई है। चारों ओर फैली अनिश्चितता के साथ परियोजना पर काम कर रहे डेवलपरों ने सौर पैनल की खरीद रोक दी है जिससे घरेलू उद्योग को भारी नुकसान हो रहा है। आयात में धीमापन आने से भी इस साल निर्धारित क्षमता तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है।

भारत में सिंगापुर एयरलाइंस की उड़ानों में कटौती

अनीश फडणीस

सिंगापुर एयरलाइंस ने कोच्चि और मुंबई जाने वाली उड़ानों में कटौती की है। कोरोनावायरस का संक्रमण बढ़ने की वजह से मांग में कटौती से मार्च में मुंबई जाने वाली चार उड़ानें और कोच्चि जाने वाली 18 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। सिंगापुर एयरलाइंस समूह भारत के 13 शहरों में हर हफ्ते 140 उड़ानों की सेवाएं देता है।

विमानन कंपनी ने अपनी वेबसाइट के एक नोटिस में लिखा है, 'कोविड-19 संक्रमण की वजह से कम मांग होने से सिंगापुर एयरलाइंस और सिल्कएयर ने अपने नेटवर्क पर सेवाएं अस्थायी रूप से कम करने का फैसला किया है। हम हालात पर नजर बनाए रखेंगे और जरूरी होने पर इसमें बदलाव करेंगे। प्रभावित ग्राहकों को सूचना दे दी जाएगी और उन्हें दूसरी उड़ानों की सेवाएं दी जाएंगी।'

फ्रैंकफर्ट, जकार्ता, लंदन, लॉस एंजलिस, पेरिस, सिओल, सिडनी और टोक्यों में उड़ानें भी रद्द की जाएंगी। मार्च-मई महीने तक के लिए सेवाएं रद्द की जाएंगी। इसके अलावा चीन और हॉन्गकॉन्ग में भी सेवाओं में कटौती करने की घोषणा की गई है।

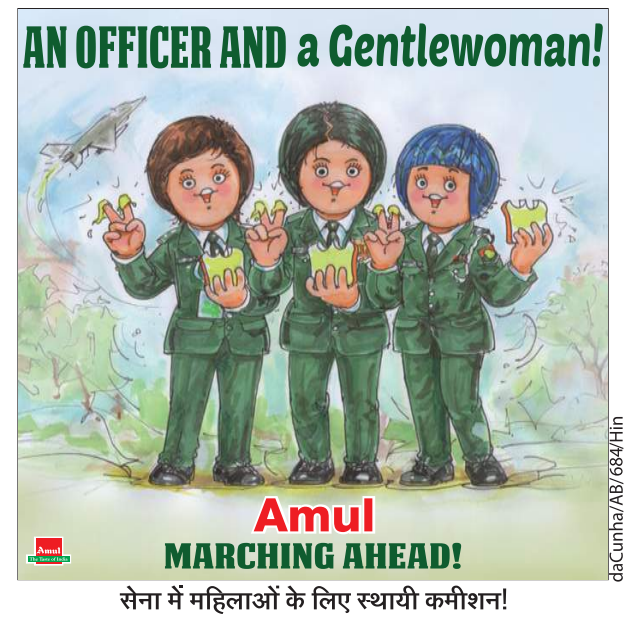

सेना में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन!

'राज्यों में हो वायरस परीक्षण प्रयोगशाला'

बीएस संवाददाता

साल 1976 में इबोला वायरस की खोज में मदद करने के लिए मशहूर बेल्जियम के माइक्रोबायोलॉजिस्ट पीटर पियट ने नए कोरोनावायरस (सीओवीआईडी-19) के लिए भारत तथा दूसरे देशों द्वारा तैयारियों को अधिक बेहतर करने के सुझाव के साथ ही कहा कि इनमें से कई देश अपने यहां इस वायरस के प्रसार की वास्तविक स्थिति के बारे में भी पूरी तरह से नहीं जानते।

नए कोरोनावायरस के कारण चीन में करीब 6 करोड़ लोगों को पूरी तरह अलग रखा गया है और 1,700 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इस समय कोरोनावायरस 25 देशों में फैल चुका है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है।

बायोएशिया सम्मेलन में 'वैश्विक स्वास्थ्य महामारी के प्रबंधन में इबोला से सीख' विषय पर बोलते हुए पीटर पियट ने कहा कि नए वायरस इन्फेक्शन के जोखिम से बचने के लिए बेहतर तैयारी ही एकमात्र तरीका है क्योंकि रोकथाम संबंधी कोई भी उपाय नए स्थानों तथा देशों में इसके विस्तार को रोक नहीं पाएगी। उन्होंने कहा कि पहले भी देशों द्वारा यात्राओं पर प्रतिबंध लगा देने से किसी महामारी के विस्तार पर पूरी तरह से रोक नहीं लग पाई।

पियट के अनुसार, नए वायरस के प्रसार की पूरी जानकारी (जैसे मृत्यु दर, संक्रमित लोगों में इसकी उपस्थिति और इलाज की कमी) आदि की समझ के अभाव में सभी वायरस के संभावित प्रसार के खिलाफ अधिक से अधिक सावधानी पर जोर दे रहे हैं।

लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन ऐंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के निदेशक और ग्लोबल हेल्थ, ब्रिटेन में प्रोफेसर पियट कहते हैं, 'अलगाव तभी कारगर होगा जब आप बहुत अधिक कुशल हैं। चीन ने कठोर नियमों को लागू करके इस महामारी पर नियंत्रण पाया है लेकिन कोई और देश इस तरह के कठोर कानून लागू नहीं कर सकता। चीन में संक्रमित लोगों की संख्या घट रही है लेकिन हम यह नहीं जानते कि संबंधित आंकड़े कितने सही हैं।' उन्होंने कहा कि वायरस के विस्तार तथा नियंत्रण के लिए अगले कुछ सप्ताह काफी अहम हैं।

अमेरिका और जापान जैसे कुछ देश ही इस महामारी के संभावित प्रसार को संभालने की स्थिति में थे और सिंगापुर जैसे कुछ देशों को यह नहीं पता था कि वे इस स्थिति में कहां खड़े हैं। उन्होंने कहा, 'मैं डरा नहीं रहा लेकिन हम जोखिम नहीं ले सकते और आग लगने से पहले एक टमॉक ड्रिल कर लेना बेहतर होता है। चीन से शुरू हुई महामारी के आर्थिक प्रभाव को भारत में महसूस किया गया है। भारत में प्रत्येक रक्त नमूने को पुणे प्रयोगशाला में भेजने के बजाए यहां के सभी राज्यों में वायरस के संक्रमण का पता लगाने में सक्षम एक प्रयोगशाला होनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि मानव इन्फ्लूएंजा वायरस वापस आने वाला था क्योंकि यह देश के टीका कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि अब तकनीक विकसित हो चुकी है और पहले के मुकाबले अब कुछ घंटों में ही नए वायरस की पहचान की जा सकती है।

ऑर्डर रद्द तो चीन के धातु निर्यातकों को धक्का

रॉयटर्स

चीन के धातु उत्पादों के कुछ वैश्विक खरीदारों ने कोरोनावायरस का संकट बढ़ने की वजह से वहां का माल लेने पर रोक लगा दी है जबकि आपूर्ति में देरी होने से कई दूसरे खरीदारों को नुकसान उठाना पड़ रहा है और वे इसकी भरपाई की मांग कर रहे हैं। चीन के एक उद्योग निकाय ने यह जानकारी दी।

रूस, तुर्की, पश्चिम एशिया और उत्तर अफ्रीका ने चीन के निर्यातकों से कह दिया है कि वे माल आपूर्ति स्वीकार नहीं करेंगे और उन्होंने खरीद को रद्द करने के लिए कहा है। यह जानकारी मेटलॉर्जिकल काउंसिल ऑफ द चाइना काउंसिल फॉर द प्रमोशन ऑफ इंटरनैशनल ट्रेड ने अपनी वेबसाइट पर दी है। इसके साथ ही भारत सहित अन्य अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों ने समय पर सामानों की आपूर्ति नहीं होने की वजह से इसकी क्षतिपूर्ति की मांग की है। हालांकि, उद्योग निकाय ने विशिष्ट कंपनियों या उत्पादों का नाम नहीं लिया है।

उद्योग समूह ने कहा कि कोरोनावायरस के फैलने की वजह से कारोबारियों के बीच होने वाली सीधी बातचीत भी ठप पड़ गई है। इस वायरस की महामारी से चीन में

- रूस, तुर्की, पश्चिम एशिया ने अपने यहां चीन से आने वाली खेप पर लगाया रोक
- आपूर्ति में देरी होने से भारत के साथ-साथ कई अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों ने क्षतिपूर्ति की मांग की
- वायरस के कारण इस्पात निर्यातकों को माल भाड़े में वृद्धि की उम्मीद
- उद्योग संगठन का मार्च में होने वाला इस्पात सम्मेलन रद्द

1,800 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। उद्योग निकाय ने कहा, 'भारत में मार्च वित्त वर्ष का अंतिम और महत्त्वपूर्ण महीना होता है जिसमें कंपनियां आगामी वर्ष के लिए अपनी खरीद योजना बनाती हैं।' उसने कहा कि चीन में स्थिति नहीं बदली तो चीनी कंपनियां व्यापार के मौके गंवा देंगी। चीन दुनिया का सबसे बड़ा धातु उपभोक्ता है लेकिन इसके साथ ही वह इस्पात और अल्युमिनियम सहित कुछ औद्योगिक धातुओं का प्रमुख निर्यातक भी है। साल 2019 में इसने करीब 370 अरब युआन मूल्य के इस्पात उत्पादों और 97.4 अरब युआन मूल्य के अल्यूमिनियम उत्पादों का

चीन में कोरोनावायरस संक्रमण से मरने वालों की तादाद 1,868 हो गई

निर्यात किया था। हालांकि, धातु उत्पादन में भारी गिरावट होने जा रही है क्योंकि कामगार वायरस की जांच की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने घर पर ही फंसे हुए हैं। वायरस के प्रसार को रोकने के लिए परिवहन में की गई कटौती के कारण कंपनियां कच्चा माल जुटा पाने या उत्पादों का निर्यात करने में भी मुश्किल का सामना कर रही हैं।

लॉजिस्टिक संबंधी मुश्किलें

परिषद ने कहा कि इस्पात निर्यातक इस बात को लेकर दुविधा में हैं कि वे समुद्री मार्ग से माल भेजें या फिर रेल के जरिये। इसकी वजह है कि अंतर्देशीय परिवहन की लागत बढ़ गई है और समुद्री बंदरगाह कम क्षमता पर परिचालित हो रहे हैं जिससे आपूर्तियों पर असर पड़ रहा है।

एक व्यापारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि डेलियन बंदरगाह पर सामान चढ़ाने और उतारने की प्रक्रिया धीमी पड़ गई है क्योंकि अन्य प्रांतों से लौट रहे कामगारों को अभी भी चिकित्सा निगरानी में ही रखा गया है। व्यापार समूह ने कहा, 'कुछ देशों ने सीमा शुल्क निकासी को बहुत अधिक कठिन बनाकर सीमा क्रॉसिंग को बंद करने की शुरुआत कर दी है।' निर्यातकों को वित्त जैसे अन्य क्षेत्रों में कर्मचारियों की कमी के कारण अव्यवस्थाओं से भी जूझना पड़ रहा है।

पूर्वी हॉन्गझोऊ शहर में एक इस्पात कारोबारी ने बताया कि उसकी कंपनी कर्ज हासिल करने में आ रही मुश्किलों के कारण कुछ निर्यात ऑर्डर को पूरा कर पाने में विफल रही। व्यापारी ने कहा, 'सामान्य तौर पर साख पत्र हासिल करने में 2 से 3 दिनों का समय लगता है लेकिन फिलहाल यह एक हफ्ते में भी मिल जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं है।'

मेटलॉर्जिकल काउंसिल के अधिकारी ने रॉयटर्स से कहा कि समूह का सालाना अंतरराष्ट्रीय इस्पात विपणन और व्यापार सम्मेलन पूर्वी शेंनडोंग प्रांत में मार्च के अंत में प्रस्तावित था जिसे इस महामारी को देखते हुए रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा भी बहुत से बड़े कार्यक्रमों को या तो रद्द कर दिया गया है या फिर आगे के लिए टाल दिया गया है।

महिला उद्यमी देंगी 15 करोड़ नौकरियां!

नेहा अलावधी

उद्यमिता क्षेत्र की महिलाएं देश में 15-17 करोड़ रोजगार के मौके तैयार कर सकती हैं जो वर्ष 2030 तक देश की कुल काम करने वाली उम्र आबादी के लिए जरूरी नौकरियों के नए मौके के मुकाबले 25 फीसदी ज्यादा है। बेन ऐंड कंपनी और गूगल की 'वुमन एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया-पावरिंग दि इकॉनमी विद हर' नाम की शीर्षक वाली एक संयुक्त रिपोर्ट के मुताबिक देश की करीब 43.2 करोड़ कार्यशील महिलाओं की आबादी है जिनमें से करीब 34.3 करोड़ कार्यशील महिलाएं ऐसे औपचारिक कार्यक्षेत्र से नहीं जुड़ी हैं जिसमें उन्हें भुगतान किया जाता हो। करीब 32.4 करोड़ महिलाएं श्रमिक बल का भी हिस्सा नहीं हैं जबकि 1.9 करोड़ महिलाएं मजदूर हैं लेकिन उन्हें कोई रोजगार नहीं मिला है।

इस रिपोर्ट के मुताबिक निजी और सरकारी क्षेत्रों द्वारा रोजगार के अतिरिक्त मौके तैयार होते हैं लेकिन देश में कार्यशील उम्र वाली महिलाओं के लिए उद्यमिता क्षेत्र में कई मौके हैं जिन्हें अब तक खंगाला नहीं गया है।

सरकारी सूत्रों के मुताबिक पिछले दशक में महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यमों की तादाद पहले के 14 फीसदी के बजाय बढ़कर 20 फीसदी हो गई है। देश में महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यमों में ज्यादा तादाद एक व्यक्ति के स्वामित्व वाले उद्यमों की है। इससे कम प्रतिफल और रोजगार के कम मौके बनते हैं। महिलाओं के स्वामित्व वाले कुल कारोबार में से केवल 17 फीसदी ही नौकरियां देते हैं। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आंकडों में महिलाओं के बीच उद्यमिता काफी ज्यादा दिखाई जाती है। देश के विभिन्न हिस्से के सर्वे के मुताबिक महिलाओं के स्वामित्व वाले 10-30 फीसदी उद्यम अक्सर महिलाओं द्वारा संचालित नहीं होते हैं।

एक अनुमान के मुताबिक देश में कार्यशील महिलाओं की आबादी करीब 43.2 करोड़ है

बेन के विश्लेषण के मुताबिक महिलाओं के वास्तविक स्वामित्व वाले और संचालित होने वाले उद्यमों की कुल हिस्सेदारी 20 फीसदी से कम रहने की संभावना है। रिपोर्ट के मुताबिक सभी राज्यों की कोशिश महिला उद्यमियों को सक्षम बनाने पर केंद्रित है ताकि इससे 5-6 करोड़ लोगों के लिए सीधे तौर पर रोजगार के मौके मिलें और 2030 तक अप्रत्यक्ष तौर पर 10-11 करोड़ लोगों को भी रोजगार दिया जा सके।फिलहाल रिपोर्ट में छह तरह की महिला उद्यमियों की पहचान की गई है। इनमें एक फीसदी वैसी ग्रामीण या शहरी महिलाएं हैं जिनका अर्द्ध-कृषि कारोबार है और वे 50 लाख से ज्यादा कमाई करती हैं और 10 से ज्यादा लोगों को रोजगार देती हैं। शहरी लघु कारोबार में करीब 6 फीसदी महिलाओं के स्वामित्व वाला कारोबार भी शामिल है जिसमें 50 लाख रुपये से कम की कमाई होती है और 10 से कम लोगों को काम मिल पाता है। इसके अलावा 8 फीसदी महिलाओं के स्वामित्व वाला कारोबार, लघु ग्रामीण गैर-कृषि स्थानीय कारोबार के जरिये संचालित होता है।

इसके अलावा दूसरी श्रेणी शहरी एकल उद्यमियों की है जिसमें 31 फीसदी महिलाओं के स्वामित्व वाला कारोबार है। शहरी, स्वरोजगार वाली महिलाएं आमतौर पर घर से काम करती हैं या अंशकालिक अवधि के लिए काम करती हैं। ग्रामीण एकल उद्यमियों में दरअसल ग्रामीण गैर-कृषि, घरेलू कारोबार करने वाले उद्यमी शामिल हैं जो खुद या सामूहिक तौर पर बिक्री कर आमदनी पाते हैं और महिला उद्यमियों के बाजार में इनकी हिस्सेदारी 38 फीसदी है। ग्रामीण क्षेत्र के कृषि उद्यमियों में महिला उद्यमियों की तादाद 16 फीसदी हैं जो कृषि आधारित कारोबार करती हैं और मुनाफे के लिए कृषि उत्पादों को उगाने और बिक्री करने पर जोर देती हैं और औपचारिक तौर पर लोगों को नौकरियां भी देती हैं।

विश्व बैंक का अनुमान

- काम करने की उम्र वाली 75 फीसदी महिलाएं भुगतान वाले काम नहीं करतीं जो देश की कार्यशील उम्र वाली आबादी का 35 फीसदी हिस्सा है
- 59 फीसदी महिलाओं के पास मोबाइल फोन की सुविधा है
- केवल 35 फीसदी महिलाएं ही सक्रियता से अपने बैंक खाते का इस्तेमाल करती हैं
- देश में खेतिहर मजदूरों में महिलाओं की तादाद 42 फीसदी तक है लेकिन महज 2 फीसदी महिलाएं ही खेत की मालिक हैं

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी का अनुमानः

- पुरुषों के मुकाबले देश की स्नातक महिलाओं के बेरोजगार होने की दर 3.5 गुना से कहीं ज्यादा है
- देश में कुल बेरोजगारी दर 7 फीसदी तक है जबकि महिलाओं में बेरोजगारी दर 18 फीसदी है
- उच्च स्तरीय शिक्षा हासिल करने वाली महिलाओं में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है